● वर्ष-3
● अंक-199
रायपुर, मंगलवार
02 अप्रैल 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं ...

पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है: मोदी

आरबीआई के कार्यक्रम में बोले मोदी- जब नीयत सही हो, तो नीति भी सही होती है

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आरबीआई दुनिया भर में अपने पेशेवर रवैये और प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के बीच समन्वय पर निर्भर है। मोदी ने कहा कि एक दशक पहले बैंकिंग क्षेत्र गहरे वित्तीय संकट में था, लेकिन अब बैंक मुनाफे में हैं और ऋण वृद्धि रिकॉर्ड स्तर पर है। उन्होंने कहा कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का बदलाव शोध का एक विषय है, सरकार ने पीएसयू बैंकों के पुनरुद्धार के लिए उनमें 3.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक के 90वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का जारी किया।

मोदी ने कहा कि आज आरबीआई एक ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गया है। इसने अपने 90 साल पूरे कर लिए हैं। एक संस्था के रूप में, आरबीआई ने स्वतंत्रता-पूर्व और स्वतंत्रता-पश्चात दोनों समय देखे हैं। आज आरबीआई अपनी व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैं आरबीआई के 90 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि आरबीआई से जुड़े लोग बहुत भाग्यशाली लोग हैं। आज वे जो नीतियां बनाते हैं, वे आरबीआई के अगले दशक के लिए रास्ता तय करेंगी। यह वह दशक है जो आरबीआई की शताब्दी का कारण बनेगा। यह दशक विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए भी महत्व रखता है। उन्होंने कहा कि इस समय जो लोग आरबीआई से जुड़े हैं, उन्हें मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं। आज आप जो नीतियां बनाएंगे, जो काम करेंगे उनसे आरबीआई के अगले दशक की दिशा तय होगी। ये दशक इस संस्थान को उसके शताब्दी वर्ष तक ले जाने वाला दशक है और ये दशक विकसित भारत की संकल्प यात्रा के लिए भी उतना ही अहम ?है। उन्होंने कहा कि मैं जब 2014 में रिजर्व बैंक के अस्सी-वें वर्ष के कार्यक्रम में आया था, तब हालात एकदम अलग थे। भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं और चुनौतियों से जूझ रहा था। एनपीए को लेकर भारत के बैंकिंग सिस्टम की स्टाबेलटी और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि आज भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया में एक मजबूत और टिकाऊ प्रणाली माना जा रहा है।

पूरे देश को मोदी की गारंटी पर भरोसा: योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रचार जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की कमान संभाल ली है। आज वह हाथरस में थे जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी ने पिछली सरकारों पर आतंक का राज कायम करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने वाले लोग भारत के विकास में बाधक हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विकसित भारत का सर्वांगीण विकास ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में हर व्यक्ति, जाति और समुदाय को बिना भेदभाव के सम्मान और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। जातिवाद और वंशवाद नहीं होना चाहिए। सबका विकास हो और यही विकसित भारत की संकल्पना का आधार है। योगी ने कहा कि पूरे देश को पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा है। बुलंदशहर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों के तहत राज्य के उथल-पुथल भरे अतीत पर अफसोस जताया और आरोप लगाया कि उन्होंने दंगा नीति अपनाई, जिससे बुलंदशहर में आतंक का राज कायम हो गया। वर्तमान स्थिति की तुलना पहले से करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोग आज नई सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं, जबकि अपराधियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पोस्टर, बैनर नहीं लगाऊंगा', गडकरी बोले-

चुनाव प्रचार के सिद्धांतों का करूंगा पालन कम से कम 5 लाख से जीतूंगा चुनाव

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल पूरी तरह से इलेक्शन के प्रचार में जुट गए हैं। इसी बीच, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रोड शो करके अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। साथ ही, गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट से कम से कम पांच लाख सीट के अंतर से जीत दर्ज करने का टारगेट सेट किया है।

गडकरी ने दावा करते हुए कहा कि वह 19 अप्रैल के चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए शहर भर में बैनर और पोस्टर नहीं चिपकाएंगे। बल्कि वोटर्स के साथ दिल से दिल और घर-घर बातचीत का रास्ता अपनाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं प्रचार के सिद्धांतो का पालन करूंगा और लोगों तक पहुंच बनाकर उनका आशीर्वाद मांगूंगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने बुजुर्ग वोटर्स से उनके घर पर जाकर मुलाकात की और उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया।

गडकरी ने कहा कि मैंने कम से कम पांच लाख वोटों के अंतर से जीतने का टारगेट सेट किया है। लोग मेरे पिछले 10 साल के काम से काफी परिचित हैं और जानते हैं कि पिछले 10 साल में मेरा कार्यकाल कैसा रहा है। पूर्व भाजपा अध्यक्ष नागपुर से लोकसभा में तीसरा कार्यकाल चाह रहे हैं। गडकरी ने 2014 के चुनाव में सात बार के लोकसभा सदस्य और कांग्रेस नेता विलास मुत्तेमवार को लगभग 2.85 लाख वोटों के अंतर करारी शिकस्त दी थी।

साल 2019 के लोकसभा इलेक्शन में गडकरी को कुल वोटों का 55.67 प्रतिशत वोट मिले, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ उनकी जीत का अंतर 2.15 लाख वोट था। इस बार के लोकसभा चुनाव में उनकी कड़ी टक्कर नागपुर शहर कांग्रेस प्रमुख और शहर के पूर्व मेयर विकास ठाकरे से होगा। ठाकरे ने कहा कि मैं एक स्थानीय नेता हूं। मैं हर गली और शहर के लोगों को जानता हूं। साथ ही जानता हूं कि चुनाव को कैसे लड़ना है।

गडकरी ने कहा कि उन्होंने नागपुर के लोगों की सेवा की है और उनकी इच्छा है कि यह एक साफ सुंदर और प्रदूषण से मुक्त शहर बनकर उभरे। गडकरी ने कहा कि मैं नागपुर के लोगों को अपना परिवार मानता हूं। आप बाहर कहीं भी जाएं किसी भी गली मौहल्ले वाले से मेरे बारे में पूछ लें। वह मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेंगे। गडकरी ने कहा कि कुछ गलत बयानों के लिए उन्हें यह तर्क दिया गया कि वह चुनाव के लिए प्रचार नहीं करेंगे या वोट नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि नागपुर के विकास के लिए काम करना है और यह तय करना उनका कर्तव्य है कि शहर को अच्छी सुविधाएं मिले।

40 साल पहले जहां थी भाजपा अब कांग्रेस वहां पहुंची

नौ उम्मीदवार तय करने में भी पार्टी के छूट रहे पसीने

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुछ सप्ताह में मतदान होना है। लेकिन बिहार में कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले दो कांग्रेस विधायक पाला बदलकर एनडीए में चले गए थे।

अब आलम यह है कि कांग्रेस को अपने हिस्से की सीटों पर चुनाव लड़वाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। महागठबंधन के सीटों बंटवारे में कांग्रेस के खाते में नौ सीटें गई हैं, जिनमें से मात्र दो पर पार्टी उम्मीदवार उतार पायी है, सात के लिए अब भी प्रत्याशियों की तलाश जारी है।

दिलचस्प है कि कांग्रेस ने दो तीन सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, वहां मुकाबला जदयू नेताओं से हैं, जबकि जिन सात सीटों पर प्रत्याशी की तलाश जारी है, उनमें से पांच पर सीधा मुकाबला भाजपा से है।

कांग्रेस ने किशनगंज से डॉ. मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर उम्मीदवार बनाया है। इन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार का मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के नेताओं से है। किशनगंज से पिछली बार कांग्रेस के मोहम्मद जावेद को ही जीत मिली थी। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी जदयू के सैयद महमूद अशरफ थे। इस बार जदयू ने किशनगंज से मुजाहिद आलम को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में जावेद को 33.92 प्रतिशत और अशरफ को 30.74 प्रतिशत वोट

मिले थे। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर का मुकाबला जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी से है। वह सीटिंग सांसद भी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में तारिक अनवर ने दुलाल चंद गोस्वामी को कड़ी टक्कर दी थी। गोस्वामी को 50.99 प्रतिशत और अनवर को 45.77 प्रतिशत वोट मिले थे।

भागलपुर से कांग्रेस अजीत शर्मा को उम्मीदवार बना सकती है। हालांकि नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है। भागलपुर में कांग्रेस के उम्मीदवार का मुकाबला जदयू नेता और सीटिंग सांसद अजय मंडल से होगा। पिछली बार यह सीट राजद के हिस्से था और शैलेश कुमार की बुरी हार हुई थी। मंडल को 61.61 प्रतिशत और कुमार को 33.69 प्रतिशत वोट मिले थे। पिछले कुछ महीनो में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के अलावा दो विधायक मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरभ ने भी कांग्रेस के किनारा कर लिया है। सीएम नीतीश कुमार के एनडीए के साथ मिलकर सरकार बनाने के दौरान दोनों कांग्रेस विधायक भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में चले गए थे। दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है।

भाजपा से मुकाबला

कांग्रेस के खाते में गई कुल नौ सीटों में से तीन पर उसका मुकाबला जदयू, पांच पर भाजपा और एक पर लोकजनशक्ति पार्टी (रामविलास) से है।

सीट	पार्टी
मुजफ्फरपुर	भाजपा
महाराजगंज	भाजपा
पश्चिमी चंपारण	भाजपा
पटना साहिब	भाजपा
सासाराम	भाजपा
समस्तीपुर	एनजेपी-आर

गन्ना बेल्ट को बनाया जाएगा ऊर्जा बेल्ट: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए ऐसा ऐलान किया है जिससे किसानों के चेहरे खिल गए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि गन्ने की खेती अब सिर्फ चीनी और गुड़ तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। गन्ना का उपयोग अब ऊर्जा के लिए भी किया जा सकेगा।

आने वाले समय में देश में गन्ना बेल्ट का विकास ऊर्जा बेल्ट के तौर पर भी किया जाएगा। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से अपनी चुनावी यात्रा का आगाज करते हुए कही है। उन्होंने ये भी कहा कि गन्ने से एथेनॉल का निर्माण होता है। इस एथेनॉल से गाड़ियों को चलाया जा सके, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। बता दें कि 10 वर्ष पहले महज 40 करोड़ लीटर एथेनॉल का निर्माण किया जाता था। मगर आज के समय में 500 करोड़ लीटर एथेनॉल का निर्माण हो रहा है। एथेनॉल के निर्माण के लिए किसानों को 70,000 करोड़ रुपये मिले है। एक समय था जब किसानों की चीनी मिलें बंद हो रही थी। इन मिलों को बेहद कम दाम पर बेचा जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किसानों पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश के किसानों को हजारों करोड़ रुपये की मदद मुहैया करवाई है। मेरठ के किसानों को किसान सम्मान निधि के जरिए 500 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि यूरिया की बोरी अन्य देशों में 3000 रुपये में मिलती है जबकि भारत में ये 90 प्रतिशत कम दाम में यानी महज 300 रुपये में किसानों को उपलब्ध कराई जा रही है। किसानों के भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए भी योजना लाई गई है।

भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए देश भर में दो लाख से अधिक गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। कम बिजली और अधिक रोशनी देने वाली एलईडी बल्ब भी किसानों को वितरित किए जाएंगे। उन्होंने अपी की कि पीएम सूर्यघर बिजली योजना का लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकेंगे। सरकार के प्रयासों की बदौलत अब किसानों को मुफ्त बिजली दी जा सकेगी।

प्रमुख समाचार

भोजशाला: वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से सुको इंकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक नहीं लगाने का विकल्प चुना है। निर्णय में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सर्वेक्षण के लिए याचिका अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर की गई थी, जिसमें प्राचीन स्मारकों के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए एएसआई के वैधानिक कर्तव्य का हवाला दिया गया था। यह निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भोजशाला मंदिर सह कमल मौला मस्जिद में वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का निर्देश देने के बाद आया है। उच्च न्यायालय के निर्देश में परिसर की आयु और संरचना निर्धारित करने के लिए जीपीआर-जीपीएस सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग सहित नवीनतम तरीकों का उपयोग करके एक व्यापक जांच शामिल थी। अदालत ने सर्वेक्षण की निगरानी करने और छह सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए एएसआई के वरिष्ठ अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया है।

चीन ने अरुणाचल को फिर से अपना हिस्सा बताया

नई दिल्ली। सीमा पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो अरुणाचल प्रदेश को लेकर बवाल कर रहा है तो दूसरी तरफ सीमा पर लगातार उसका निर्माण कार्य भी जारी है। चीन ने अरुणाचल को फिर से अपना हिस्सा बताने की हिमाकत की है। अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों के चाइनीज नाम जारी किए गए हैं। भारत चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने को खारिज करता रहा है, यह कहते हुए कि राज्य देश का अभिन्न अंग है और आविष्कृत नाम निर्दिष्ट करने से इस वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं आता है। चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने ज़ंगनान में मानकीकृत भौगोलिक नामों की चौथी सूची जारी की, जो अरुणाचल प्रदेश का चीनी नाम है, जिसे बीजिंग दक्षिण तिब्बत के हिस्से के रूप में दावा करता है। चीन का पलटवार करने के लिए भारत भी खुद को और भी मजबूत बना रहा है। भारत भी लगातार कुछ सालों से चीन से लगी सीमा पर नए बुनियादी ढांचे का निर्माण तेजी से कर रहा है। जिनमें से अधिकांश अब पूरा होने की कगार पर है।

पूर्व स्पीकर इरेंगबाम हेमोचंद्र सिंह ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी

नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका देते हुए, मणिपुर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मंत्री इरेंगबाम हेमचंद्र सिंह ने जल्दबाजी में पार्टी छोड़ दी। चुनाव प्रचार के बीच यह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है, जिससे पूर्व स्पीकर जुड़े हुए थे। 59 वर्षीय हेमोचंद्र, सिंगजामेई से पांच बार विधायक हैं और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कीशम मेघचंद्र सिंह को सौंपते हुए कहा कि वह पार्टी में अपने विश्वास और विश्वास की पूरी कमी को व्यक्त करना चाहते हैं। विधायक ने कहा कि मैंने भारी मन से यह निर्णय लिया। मणिपुर में कांग्रेस की कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने पार्टी को पतवारहीन और डूबता जहाज करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कांग्रेस नेताओं के लिए प्रतिभा और ईमानदारी महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस ने आंतरिक मणिपुर संसदीय सीट से जेएनयू के प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम और अनुसूचित जनजाति आरक्षित बाहरी मणिपुर क्षेत्र से पूर्व विधायक अल्फ्रेड कन्नगम एस आर्थर को मैदान में उतारा है।

पाटिल और चव्हाण को लेकर सतारा पर सस्पेंस बरकरार

मुंबई। सतारा लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार पार्टी से कौन होगा उम्मीदवार? इस संबंध में अभी भी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि मौजूदा सांसद श्रीनिवास पाटिल ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। श्रीनिवास पाटिल के इनकार के बाद शरद पवार सतारा में नए उम्मीदवार की तलाश में हैं और इस सीट से पृथ्वीराज चव्हाण का नाम सामने आ रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने पृथ्वीराज चव्हाण से मुलाकात की, इसलिए इन चर्चाओं पर विराम लग गया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने आखिरकार सतारा के उम्मीदवार को लेकर खुलासा कर दिया है। इस सीट पर एनसीपी का कब्जा है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि लगभग सभी 48 सीटों पर सहमति है, सतारा सीट एनसीपी की है, मैंने जयंत पाटिल से चर्चा की है, शरद पवार यह फैसला लेना चाहते हैं। पृथ्वीराज चव्हाण ने एक सुझावात्मक बयान भी दिया है कि अगर मुझे आदेश दिया जाए तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन शरद पवार यह फैसला देना चाहते हैं.

अपने भ्रष्टाचार से आम जनता को भटकाना चाह रहे हैं: बांसुरी

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा मंत्री एवं नई दिल्ली लोकसभा से सांसद प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आज एक संवाददाता सम्मेलन कर कल हुई इंडी गठबंधन की रैली को एक भ्रष्टाचारियों का संगठन बताया जिसमें ना ही कोई सामंजस्य था और ना ही उसका आम जनता से कोई लेना देना बल्कि वह सिर्फ अपने भ्रष्टाचारों को छिपाने और जनता को मुख्य मुद्दों से भटकाने के लिए एक प्रोपगेंडा था। प्रेस वार्ता का संचालन कर रहे दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर ने कहा की कल हमने देखा की यह राजनीतिक गठबंधन नही है यह तो ठगबंधन है जो औरों साथ एक दूसरे को भी ठग रहा है जैसे कल कांग्रेस ने मंच से अरविंद केजरीवाल की तस्वीर का बोर्ड हटवा कर कर दिखाया। प्रेसवार्ता में प्रदेश प्रवक्ता श्री अजय सहरावत, मीडिया रिलेशन विभाग प्रमुख श्री विक्रम मित्तल और प्रदेश सोशल मीडिया प्रमुख डॉ रोहित उपाध्याय उपस्थित थे। बांसुरी स्वराज ने कहा कि कल रामलीला मैदान में रैली नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का एक फ्लॉप शॉ देखा गया जिसमें सबने देखा कि जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे उस वक्त पूरी की पूरी कुर्सियां खाली थी जो बताती है कि इस रैली को जनता का समर्थन नहीं मिल पाया।

44 दिनों तक चलेगा सत्ता का संग्राम, इतिहास में दूसरा सबसे लंबा लोकसभा चुनाव

नई दिल्ली। देश में इन दिनों लोकसभा चुनावों की सरगर्मी है। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रमों की घोषणा की थी। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच देश में सात चरण में चुनाव होने हैं। देश के चुनावी इतिहास का यह दूसरा सबसे लंबा चुनाव है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही मतदान की प्रक्रिया 1 जून तक चलेगी। इस तरह से मतदान कराने में कुल 44 दिन का समय लगेगा।

पहले चुनाव में लग गए थे चार महीने- 1951-52 के दौरान चुनाव की प्रक्रिया में कुल 120 दिन लगे थे। हिमाचल प्रदेश की चिनी तहसील के मतदाताओं ने देश में सबसे पहले 25 अक्तूबर 1951 को वोट डाला था। 25 अक्तूबर की सुबह छह बजे शुरू हुआ मतदान 27 अक्तूबर तक जारी रहा था। महासू जिले की चिनी तहसील के साथ ही चंबा जिले की पांगी तहसील में भी 25 अक्तूबर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई जो 2 नवंबर तक जारी रही। इस दौरान इन दोनों तहसील के 20 हजार मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन दो तहसील के अलावा बाकी हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया 19 नवंबर से शुरू हुई। देश के बाकी मतदाताओं ने जनवरी-फरवरी 1952 में मतदान किया। 21 फरवरी 1952 को आखिरी चरण के वोट डाले गए। इस तरह मतदान की पूरी प्रक्रिया 120 दिन चली।

दूसरे आम चुनाव में कम देरी- 1957- चुनाव आयोग 1957 के लोकसभा चुनावों की लिए पहले से तैयार था। हिमाचल प्रदेश और पंजाब की पहाड़ियों में कुछ बर्फ से ढके निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर, शेष भारत में 24 फरवरी से 15 मार्च, 1957 के बीच 20 दिनों के भीतर मतदान की प्रक्रिया को पूरा किया गया था।

1962- देश के तीसरे आम चुनाव में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ मतदान हुआ था। मतदाताओं ने 16 और 25 फरवरी, 1962 के बीच अधिकांश भाग के लिए मतदान किया था। यानी दस दिनों की अवधि में तीसरे लोकसभा चुनाव कराए गए थे।

1967- तीसरे आम चुनाव के समय 494 लोकसभा सीटें अस्तित्व में थीं, लेकिन चौथे आम चुनाव में यह संख्या बढ़कर 520 हो गई। इस बार भी

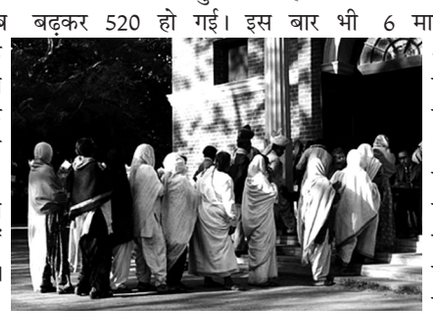

लोकसभा के साथ राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए थे। 1967 में लोकसभा के चुनाव में मतदान की प्रक्रिया महज सात दिन में पूरी कर ली गई थी।

1971- पांचवें लोकसभा के चुनाव में मतदान 1 मार्च 1971 से शुरू होकर 6 मार्च 1971 तक कराए गए थे। अधिकांश भाग के लिए छह दिन में मतदान पूरा कर लिया गया था। केरल में 3 मार्च और 6 मार्च, 1971 मतदान की तारीखें थीं लेकिन राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों और सरकारी स्कूल की शिक्षकों की हड़ताल की वजह से 6 मार्च और 9 मार्च, 1971 को चुनाव कराने पड़े थे। इस तरह से मतदान नौ दिन के भीतर पूरा कर लिया गया था।

जब आपातकाल के बाद हुए चुनाव-1977- 1971 के बाद अगले लोकसभा के चुनाव 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद कराए गए थे। नौ राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में एक दिन में, 11 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में दो दिनों में और दो राज्यों में तीन दिनों में मतदान पूरा हुआ था। इस तरह से छठे लोकसभा के चुनाव में मतदान महज छह दिन में हो गए थे।

1980 में दो दिन मतदान, अवधि केवल चार दिन- 1980 यानी सातवें लोकसभा के चुनाव मात्र दो दिन में हो गए थे। ऐसा पहली बार हुआ कि पूरे देश में केवल दो दिन ही मतदान होना तय हुआ। वहीं पूरी प्रक्रिया की अवधि केवल चार दिन थी। 17 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 10 जनवरी 1980 से पहले चुनाव संपन्न हो गए थे।

1984 में आठवीं लोकसभा के चुनाव हुए थे। इसके लिए 24 और 27 दिसंबर, 1984 को मतदान हुआ था। पंजाब और असम में मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण मतदान नहीं हुआ था। ये चुनाव बाद में कराए गए थे।

1989- नौवीं लोकसभा के चुनाव कई मायनों में अलग थे। इससे पहले 1988 में 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया जिससे मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतदान 22-26 नवंबर 1989 के बीच हुए थे। यानी मतदान की प्रक्रिया पांच दिन चली।

टेटमड़गु के जंगल में मुठभेड़, 1 नक्सली ढेर

सुकमा। सुकमा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती टेटमड़गु इलाके में सोमवार को जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों के खिलाफ जवाबी फायरिंग में सुरक्षाबल के जवानों ने एक नक्सली मार गिराया है। मृतक नक्सली की पहचान नहीं हो पाई है। घटनास्थल से हथियार और भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी बरामद की गई है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार को सुकमा के किस्टाराम पुलिस थाना क्षेत्र के जंगल में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), कोबरा 208 और सीआरपीएफ 204 बटालियन की टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। इसी दौरान नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। सुरक्षाबलों के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों पर जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में एक माओवादियों के मारा गया है।

सुकमा एसपी किरण जी चव्हाण ने नक्सली मुठभेड़ की पुष्टि की है। लेकिन कुछ भी स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी गई है। पुलिस का कहना है कि सर्चिंग पार्टी के लौटने के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। सुरक्षाबल के जवान घटनास्थल के आसपास सर्चिंग कर रहे हैं। जवानों ने घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और नक्सल सामग्री भी बरामद की है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पुलिस के अनुसार, सुकमा सहित सात जिलों वाले बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ अलग-अलग मुठभेड़ों में इस साल अब तक 33 नक्सली मारे गए हैं। आपको बता दें कि सुकमा

जिला बस्तर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा।

दंतेवाड़ा में नक्सली कमांडर ने किया सरेंडर, लोन वर्राटू अभियान से था प्रभावित

दंतेवाड़ा। जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू अभियान (घर वापस आईये अभियान) से प्रभावित होकर एक नक्सली कमांडर ने आत्मसमर्पण किया है। डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा पहुंचकर नक्सली राजू माड़वी ने पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने कहा है कि समर्पित नक्सली को छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास योजना के तहत प्रोत्साहन राशि एवं पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति और लोन वर्राटू अभियान (घर वापस आईये अभियान) से प्रभावित होकर 1 अप्रैल को नक्सली कमांडर ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सली कमांडर का नाम राजू माड़वी है, जो भैरमगढ़ एरिया कमेटी के हुर्रेपाल पंचायत मिलिशिया प्लाटून सेक्शन बी में कमांडर के पद पर सक्रिय था। उसने पुलिस अधीक्षक गौरव राय के समक्ष डीआरजी कार्यालय दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पण किया है।

एसपी गौरव राय ने कहा आत्मसमर्पित नक्सली को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास योजना के तहत 25 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि और मिलने वाले सभी प्रकार का लाभ प्रदाय कराया जायेगा। दरअसल, जिले में दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 174 ईनामी नक्सली सहित कुल 686 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। जिसके बाद वे सभी समाज के मुख्यधारा से जुड़कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।

लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा गांव-गांव घूमकर मांग रहे वोट

जगदलपुर। हमेशा से अपने बयानों के साथ ही लोगों के साथ हर माहौल में अपने आप को ढालने वाले कांग्रेस के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। एक ओर जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी गांव-गांव घूमकर अपने लिए वोट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा रविवार को पुसपाल के बाजार में मुर्गा लड़ाई करते हुए दिखाई दिए।

बताया जा रहा है कि बस्तर में पहले चरण में चुनाव होना है, ऐसे में पार्टियों के द्वारा अपने लोकसभा चुनाव के लिए तय किये गए प्रत्याशियों के लिए स्टार प्रचारक के साथ ही अन्य नेताओं का बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों में रोजाना डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि वे अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी दिलाते हुए लोकसभा चुनाव में विजयी बनाया जा सके, इसके लिये पार्टियों की ओर से कमर भी कस ली गई है। रोजाना सघन अभियान भी चलाया जा रहा है।

वहीं इन लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सुकमा जिले के छह बार के विधायक

रह चुके कवासी लखमा को एक बार लोकसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित किया है।

ऐसे में कवासी लखमा इन शोर गुल से हटकर रविवार को पुसपाल के बाजार पहुंचे और वहां होने वाले मुर्गा लड़ाई में जमकर हिस्सा लेते हुए मुर्गा लड़ाई भी की। मुर्गा लड़ाई के दौरान लोगों के द्वारा कवासी लखमा को अपने पास देख लोगों ने जमकर उनका उत्साहवर्धन करने के साथ ही मुर्गा लड़ाई में उनके द्वारा लड़ाए जा रहे मुर्गे की जीत को लेकर समर्थन भी किया।

बता दें कि कवासी लखमा हमेशा से लोगों के बीच सुर्खियों में रहे हैं, जिसमें बस्तर में आये डांसर धर्मेश के साथ जमकर मंच पर थिरकने के साथ ही बस्तर में डांस को बढ़ावा देने की बात कही, तो वही ग्रामीण इलाकों में घूमने के दौरान एक ग्रामीण के द्वारा पी जा रही बीड़ी को ही बीड़ी से जालते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा एक महिला के घर मिलने जाने के बाद उनके ही घर में लगे आइने में अपने आप को देखने के बाद वहीं कंघी भी कर अपनी सुंदरता को लेकर बात कही, कभी बैगा गुनिया बन अपने आप को कोड़े भी मारते हुए वीडियो भी वायरल हुआ।

शिवलिंग जलहरि न उखाड़ पाए तो गतेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग ही ले गए चोर

बिलासपुर। ग्राम ओखर में स्थित गतेश्वर महादेव मंदिर में रविवार की रात चोरों ने धावा बोला और मंदिर के शिवलिंग जलहरि को उखाडऩे का प्रयास किया लेकिन उससमें सफल नहीं होने पर शिवलिंग को ही ले गए। सोमवार की सुबह इसकी जानकारी गांव के लोगों को हुई और इसकी सूचना पचपेड़ी पुलिस को दी गई। चोरों की तलाश में पुलिस जुट गई है।

पचपेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम ओखर स्थित गतवा तालाब के तट में गतेश्वर महादेव मंदिर है जहां गांव के लोग पूजापाठ करते हैं। गांव में रहने वाला गुहलेत साहू सोमवार की तड़के चार बजे मंदिर पहुंचा, इस दौरान शिवलिंग गायब था। उसने इसकी जानकारी गांव के लोगों को दी और देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। घटना की सूचना पर पचपेड़ी पुलिस की टीम वहां पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरु की लेकिन चोरों की पता नहीं लग पाया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही वे चोर को गिरफ्तार कर लेंगे।

मंदिर परिसर में साहू समाज की ओर से सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। कुछ दिन पहले बंदरों के उत्पात के कारण सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। इधर चोरों ने केवल शिवलिंग की चोरी की है। मंदिर में रखा दानपेटी सुरक्षित है। इससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि चोर शिवलिंग को महंगा

पत्थर समझकर ले गए हैं। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव में लगे एक घर के सीसी टीवी कैमरा को चेक किया। इसमें पता चला कि रात 1:40 बजे के आसपास बाइक में सवार दो व्यक्ति संदिग्ध रूप से गांव में घूम रहे थे। दोनों टोपी पहने हुए है और मुंह को बांध रखे है। आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने ही मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है।

उल्लेखनीय हैं कि गांव के लोगों को तालाब की खोदाई के दौरान काले ग्रेनाइट की जलहरि मिली थी। इसके ऊपर शिवलिंग नहीं था। भारत को आजादी मिलने के बाद गांव के कपिल नाथ पांडेय शिवलिंग लाने के लिए मध्यप्रदेश के भेड़ाघाट गए थे। शिवलिंग लेकर वे ट्रेन से बिलासपुर तक आए। तब यातायात के साधन नहीं होने के कारण वे पैदल ही गांव पहुंचे। इसके बाद गांव के लोगों के साथ श्रद्धापूर्वक शिवलिंग को स्थापित किया गया था। इसके बाद से ही गांव के लोग श्रद्धा पूर्वक मंदिर में पूजा-पाठ करते हैं।

दादरगढ़ स्थित चेकपोस्ट में लग्जरी कार से 1 लाख 63 हजार जब्त

कांकेर। केशकाल विकासखंण्ड अंर्तगत दादरगढ़ स्थित चेकपोस्ट में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 24 घण्टे राष्ट्रीय राजमार्ग में आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। रविवार रात करीब 10 बजे कार्यवाही के दौरान एसडीएम अंकित चौहान व थाना प्रभारी सौरभ उपाध्याय की मौजूदगी में एफएसटी की टीम ने एक लग्जरी कार से 1 लाख 63 हजार 500 रुपए जब्त किए है। चूंकि कार में बैठे युवकों से पूछताछ करने पर वह पैसे के संबंध में किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप एफएसटी की टीम के द्वारा उक्त राशि को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार टोयोटा हाईराइडर कार क्रमांक सीजी 06 जिएक्स 9363 में सवार 2 युवक

मोहित जैन निवासी महासमुंद व मनीष जैन निवासी रायपुर की कार को दादरगढ़ चेकपोस्ट में रोक कर तलाशी ली गई। जहां एसडीएम, थाना प्रभारी समेत अन्य स्टाफ द्वारा जांच के दौरान उन्हें एक थैले में नकदी रकम 1,63,500 रुपए बरामद हुआ। लेकिन नगद रकम से सम्बंधित किसी प्रकार के दस्तावेज नही होने के कारण उक्त नगद राशि को जब्त कर जिला स्तरीय समिति को आगामी निर्णय हेतु अग्रेषित किया गया है।

आरपीएफ टीम को दुर्ग रेलवे स्टेशन में लावारिस हालात में मिले 12 बच्चें

■ **पुलिस ने चाइल्ड हेल्प लाइन को सौंपा**

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में 12 बच्चों को रेलवे पुलिस ने रेस्क्यू किया है। ये बच्चे लावारिस हालात में पाए गए। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे हैदराबाद स्थित बालाजी गुरुकुल के बच्चे हैं। सभी की उम्र 8 से 15 साल के बीच है। इन बच्चों को रेलवे पुलिस ने चाइल्ड हेल्प लाइन को सौंप दिया है। फिलहाल हैदराबाद और बिलासपुर के कुछ परिजनों से पुलिस ने सम्पर्क कर दस्तावेज प्रस्तुत कर बच्चों को ले जाने के लिए दुर्ग बुलाया है।

दुर्ग रेलवे स्टेशन में मिले इन बच्चों में असम, नागालैंड और छत्तीसगढ़ के बच्चे शामिल हैं। रेलवे पुलिस के अनुसार, आरपीएफ टीम रविवार को स्टेशन में सर्च कर रही थी। इसी दौरान प्लेटफार्म नंबर-4 पर बैठे बच्चों पर उनकी नजर पड़ी, जिनके साथ कोई पेरेंट्स नहीं थे। बच्चों से पूछताछ करने के बाद बच्चों को स्टेशन के कमरे में लाया गया और अफसरों को इसकी सूचना दी गई।

पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे हैदराबाद

स्थित बालाजी गुरुकुल के छात्र हैं और सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस से दुर्ग पहुंचे हैं। उनको अंबिकापुर में होने वाले योग कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। इन बच्चों के साथ स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई नहीं था। ऐसे में जवानों ने बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन की मदद से आश्रय गृह भेज दिया है।

आरपीएफ दुर्ग के प्रभारी एसके सिन्हा ने बताया कि, ये बच्चे देश के अलग-अलग हिस्सों से आए हैं। इनमें 3 बच्चे झारखंड, 2 नागालैंड, एक असम और 6 बच्चे छत्तीसगढ़ से हैं। प्रदेश के 6 बच्चों में 3 रायगढ़, 1-1 पेंड्रा, बलौदा बाजार और जशपुर के शामिल हैं। अफसरों का कहना है कि बिलासपुर से कुछ परिजन दुर्ग पहुंच रहे हैं। सभी दस्तावेजों के जांच के बाद उन्हें बच्चों को सौंप दिया जाएगा।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

रिवाल्वर दिखाकर की लूटपाट भागने पर लोगों ने दबोचा

बलरामपुर रामानुजगंज। बलरामपुर रामनुजगंज चांदो थाना अंतर्गत ग्राम जरहाखाड पहाड़ी कोरबा से 800 रुपये नगद एवं मोबाइल लूटने वाले तीन युवकों को पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से धर दबोचा। जिनके खिलाफ धारा 341,294, 392, 397,506 34 आईपीसी और 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया और इसके बाद तीनों को न्यायालय पेश किया गया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम मगजी के रहने वाले पहाड़ी कोरबा प्रभु बेसरा बसकेपी में बाजार कर 30 मार्च के देर शाम 6:30 बजे करीब अपने गांव मगाजी स्कूटी से जा रहा था। इसी दौरान विवेकानंद चौबे पिता अनिल चौबे उम्र 24 वर्ष निवासी गोदरमान, समीर कुशवाहा पिता रामचंद्र कुशवाहा उम्र 18 वर्ष वार्ड क्रमांक 14 रामानुजगंज निवासी एवं राकेश यादव रामानुजगंज निवासी तीनों युवक के द्वारा जो पल्सर मोटरसाइकिल में थे। तीनों ने प्रभु बेसरा को रोका और रिवाल्वर दिखाकर 800 रुपये, एंड्राइड सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन लूट लिया।

डिप्टी कलेक्टर के चेम्बर में लगी आग, दस्तावेज राख

कोरबा। कोरबा जिले में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, इस बार आग कलेक्टोरेट परिसर में लगी है। डिप्टी कलेक्टर विकास चौधरी के चेंबर में भीषण आग लग गई। एसी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आगजनी की घटना हुई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट में हड़कंप मच गया और लोग बाहर निकल गए। आगजनी की घटना में डिप्टी कलेक्टर के चेंबर में रखे फर्नीचर और अहम दस्तावेज पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह 10:30 पर जब अधिकारी कर्मचारी कलेक्ट्रेट में काम करने पहुंचे इस दौरान डिप्टी कलेक्टर की चेंबर में धुआं उठता देख लोगों ने इसकी सूचना दमकल वाहन को दी। जहां मौके पर तत्काल दमकल वाहन मौके पर पहुंची और आज पर काबू पाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट होने के बाद दस्तावेज में पहले आग लगी उसके बाद आसपास सामानों में धीरे-धीरे आग बढ़ती गई, इसके बाद अफरा तफरी मच गई।

कुसमुंडा खदान में डंफर में लगी भीषण आग

कोरबा। जिले के कुसमुंडा खदान में पुराने तीन नम्बर वर्कशॉप में खड़ी 100 टन वजनी क्षमता वाले विमल कंपनी के डंफर में भीषण आग लग गई। आग से उठने वाली धुएं का काला गुब्बार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि ये डंफर सर्विस ऑफ हो चुके हैं। जारी निविदा के तहत इनकी कटिंग का कार्य चल रहा था। ठेका कर्मचारियों द्वारा इन डंफरों से बिना ज्वलनशील सामान निकले ही गैस युक्त कटिंग मशीनों द्वारा कटिंग किया जा रहा था, जिससे चिंगारी संभवत: डंफर के टायर और डीजल चेंबर में जा पहुंची। जहां से आग ने पूरे डंफर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही विभागीय फायर ब्रिगेड के वाहन मौके पर पंहुचे और आग पर काबू पाया गया। जिस तरह से आग की लपटे उठी थी। आसपास अन्य मशीनों को अपनी चपेट में ले सकती थी। जनहानि भी हो सकती थी। निश्चित रूप से इस घटना में जिम्मेदार लापरवाह ठेका कंपनी के खिलाफ प्रबंधन को सख्ती बरतनी चाहिए।

दो पीड़ितों से लाखों की वसूली नेता-पुलिस सब शामिल

बालौदबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में देह व्यापार का भंडाफोड़ हो गया है। देह व्यापार के नाम पर पत्रकार, नेता और पुलिस ने मिलकर लोगों से लाखों रुपये वसूले हैं। शहर के ही दों पीड़ितों से 25 लाख रुपये की वसूली किए जाने का मामला आया सामने आया। जिसके बाद इस रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं को पीड़ितों के घर में भेजा जाता था और उससे देह व्यापार के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी। आरोपियों द्वारा दबावपूर्वक, अपराधिक षड्यंत्र करते हुए मोटी रकम उगाही की जाती थी। मुख्य सरगना मोंटी उर्फ प्रत्यूष मरैया, दुर्गा टंडन, शिरीष पांडे, महान मिश्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस की जांच शुरू होते ही आरोपी फरार हो गए। फिलहाल, सिटी कोतवाली पुलिश जांच में जुटी हुई है।

वांछित आरोपी की जगह भाई को पकड़ लाई कोरबा पुलिस

कोरबा। दर्री थाना के प्रभारी प्रशिक्षु अधिकारी अविनाश कंवर ने एक कथित बेकसूर युवक पर अपना गुस्सा उतार दिया। इतना ही नहीं उसकी बुरी तरह से पिटाई भी की। दर्री थाना प्रभारी पर क्रूरता का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने उन्हें मनोरोगी तक करार दे दिया। बताया गया कि महिला संबंधी अपराध के मामले में दर्री पुलिस को आरोपी नहीं मिला तो उसके भाई को ही पकड़कर के लाये और कमरे में बदं कर जमकर पिटाई कर दी। इस युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। एरिगेशन कालोनी निवासी पीड़ित ने बताया कि थाना प्रभारी अविनाश कंवर ने भाई के न मिलने पर प्रभारी और पुलिस कर्मियों ने उसके साथ पिटाई की है। पीड़ित के पीठ और कमर के नीचे गंभीर चोट दिख रही है। पीड़ित के भाई के नाम से एक महिला ने शिकायत की थी। शराब पीकर पीड़ित का भाई गाली गलौज कर रहा था। पीड़ित ने बताया कि उसने आरोपी का घर तक दिखाने में पुलिस को सहयोग किया था। पीड़ित की मानें तो उसकी भाई को पकड़ने पुलिस आई हुई थी।

पीडब्ल्यूडी एसडीओ के गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट हुआ नाराज

बिलासपुर। बिलासा देवी एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विस्तार के लिए बिलासपुर के पत्रकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट पेश कर कोर्ट को जानकारी दी कि 19 मार्च को बाउंड्रीवाल निर्माण पूरा होने की गलत जानकारी कोर्ट को दी गई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीडब्ल्यूडी के एसडीओ आदित्य ग्रोवर को तलब कर जमकर फटकार लगाई। साथ ही अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एसडीओ के इस हरकत को न्याय के क्षेत्र में गलत हस्तक्षेप माना है। मामले में 10 अप्रैल को अगली सुनवाई है।

दरअसल, बिलासपुर के बिलासा देवी एयरपोर्ट और हवाई सेवा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पुनर्विचार कर सुविधाएं बढ़ाने

को लेकर लगी है। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू किए जाने को लेकर पत्रकार ने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका में सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नियुक्त कोर्ट कमिश्नर एयरपोर्ट में यात्री सुविधाओं के साथ सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम का निरीक्षण किया था। साथ ही कोर्ट में रिपोर्ट पेश की थी। कोर्ट में पीडब्ल्यूडी के एसडीओ ने पूर्व में जानकारी दी थी कि एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए रनवे और इससे जुड़ी दूसरी जगह पर बाउंड्री वॉल तैयार कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से कोर्ट को यह पता चला कि बाउंड्री वॉल का काम पूरा नहीं हुआ है और कोर्ट को गलत जानकारी दी गई। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट पर कोर्ट पीडब्ल्यूडी के एसडीओ की गलत जानकारी देने पर काफी नाराजगी जाहिर की। साथ ही मामले में एसडीओ आदित्य ग्रोवर को तलब कर जमकर फटकार लगाई। इसके साथ ही कोर्ट को गलत जानकारी देने के मामले में एसडीओ को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने एयरपोर्ट में निरीक्षण के दौरान पाया कि यात्री सुविधा और फ्लाइट की लिए सुरक्षा के इंतजाम में खामियां हैं। इसे लेकर भी कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही सुविधाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी।

मिली जानकारी के मुताबिक पत्रकार ने अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव के माध्यम से हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश कर बिलासपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग साल 2017 में की थी। लंबी लड़ाई और हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद 1 मार्च से उड़ान शुरू हुई। हवाई सेवा शुरू करने के लिए हाईकोर्ट में पहले भी जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को दिशा-निर्देश के साथ निराकृत कर दिया था, लेकिन 9 महीने बाद भी हवाई सेवा शुरू न होने की वजह से याचिकाकर्ता कमल दुबे ने दोबारा पीआईएल को रिवाइव करने के लिए आवेदन दिया था। इसे हाईकोर्ट ने बीते दिनों स्वीकार कर लिया। अब रिवाइव हो जाने के बाद जनहित याचिका पर दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है।

एक्शन मोड में पुलिस, चोर गिरोह का किया भंडाफोड़

दुर्ग भिलाई। जिले में सुपेला थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में पिछले दिनों हुई दो चोरी केस में पुलिस के बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दो मकानों में चोरी करने वाले तीन अपचारी समेत पांच चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों से सोने-चांदी के आभूषण और जले हुए कापर केबल का तांबा जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत दो लाख पांच हजार रुपये आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता स्मिता ठाकुर ने पुलिस से शिकायत की थी कि उसके नेहरू नगर स्थित मकान में डॉ नितेश नामदेव किराये पर रहते हैं। वे एक सप्ताह के लिए बाहर गए हुए थे। किरायेदार डॉ नितेश के मकान में 27 से 29 मार्च के बीच किसी अज्ञात आरोपित ने चोरी कर ली है। चोरों ने घर का ताला तोड़कर आलमारी में रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज किया और आरोपियों की पतासाजी शुरू की थी। टीआई राजेश मिश्रा ने

कहा पुलिस ने जांच के दौरान संदेह के आधार पर अटल आवास नेहरू नगर निवासी दुर्गा साहू (47) को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ में उसने अपने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर नेहरू नगर स्थित मकान में घुसकर सोने चांदी के जेवर चोरी करने की बात स्वीकार की। आरोपियों के पास से चोरी का जेवर बरामद किया गया है। जिसकी कीमत 1 लाख 88 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस के अनुसार, इसी तरह से सुपेला थाना क्षेत्र के नेहरू नगर पश्चिम निवासी संजय अग्रवाल ने शिकायत की थी कि 25 मार्च की रात को उनके घर की बाउंड्रीवाल के अंदर रखे केबल तार के बंडल को अज्ञात आरोपित ने चोरी कर लिया है।

संक्षिप्त समाचार

पूर्व सीएम बघेल कल दाखिल करेंगे नामांकन, 4 को भाजपा से संतोष पांडेय

राजनांदगांव। राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं 4 अप्रैल को सांसद और भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडेय नामांकन जमा करेंगे, इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नामांकन रैली में शामिल होंगे। भूपेश बघेल कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर 2 अप्रैल को अपने 5 समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन जमा करने के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस समेत समूचे लोकसभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। स्थानीय स्टेट हाईस्कूल में नामांकन जमा करने से पूर्व एक बड़ी सभा होगी जिसे प्रदेश प्रभारी पायलट संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। इसके बाद एक भव्य रैली शहर में भ्रमण करेगी। रैली कलेक्टोरेट परिसर में जाकर समाप्त होगी। 4 अप्रैल को सांसद संतोष पांडे भी नामांकन जमा करेंगे। नामांकन जमा करने से पहले रैली के माध्यम से कलेक्टोरेट परिसर पहुंचेंगे, इस रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, प्रदेश के गृहमंत्री व प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के अलावा अन्य प्रमुख नेता भी उपस्थित रहेंगे।

एक दिन में ही 15 करोड़ का मिला राजस्व आधी रात तक हुई रजिस्ट्री

रायपुर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम दिन रविवार को प्रदेश के सभी पंजीयन कार्यालय देर रात तक खुले रहे। रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित पंजीयन कार्यालय भी जमीन की रजिस्ट्री कराने लोगों की भीड़ लगी रही। यहां रात 1 बजे तक रजिस्ट्री का काम हुआ। एक दिन में ही रायपुर में 15 करोड़ राजस्व की प्राप्त हुई है। पिछले बार 9 करोड़ का ही राजस्व की प्राप्ति हुई थी। बता दें कि 2022-23 वित्तीय वर्ष में 94 करोड़, 18 लाख से ज्यादा की आय हुई थी। वहीं 2023-24 में 1 अरब 22 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिला है। 34% प्रतिशत छूट बंद होने का असर जनता की जेब पर पड़ेगा। 1 अप्रैल से आम जनता को 10 लाख की जमीन खरीदने पर एक लाख 10 हजार से ज्यादा स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क देना पड़ेगा। 30 फीसदी गाइडलाइन की छूट समाप्त करने से किसानों को लाभ मिलेगा, जबकि अधिग्रहण के मामले में 30 फीसदी छूट का कोई असर पहले भी नहीं पड़ता था, अब भी नहीं पड़ेगा। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 25 जुलाई 2019 को कलेक्टर गाइडलाइंस में 30% की छूट का आदेश राज्य भर में लागू किया था। इससे 5 सालों में ज़मीन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए यानी 1 करोड़ की ज़मीन 70 लाख में खरीदी जाती थी, लेकिन अब प्रदेश की सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से इस आदेश को आगे जारी न रखने का फ़ैसला कर लिया है, जिससे अब प्लॉट, ज़मीन और मकान की कीमतें भी बढ़ जाएंगी।

टूटेजा पिता-पुत्र के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर कोर्ट ने लगायी रोक

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उसके बेटे यश टुटेजा के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ज्ञात हो कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए कथित शराब घोटाले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू की थी, जिसे कुछ दिनों पहले राज्य सरकार की एजेंसी एसीबी और ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व में शराब घोटाले में ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर कार्रवाई पर रोक लगाई जा चुकी थी। एसीबी की जांच शुरू होने पर टुटेजा ने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, मगर शीर्ष कोर्ट हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। हाईकोर्ट में टुटेजा की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से उनके अधिवक्ता राजीव श्रीवास्तव व सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि पूर्व में इसी मामले में नोएडा, यूपी में अपराध दर्ज किया जा चुका है। एक ही मामले में दो अपराध दर्ज नहीं किए जा सकते।

छत्तीसगढ़ में महंगी हुई रेत, शराब और जमीन की रजिस्ट्री

■ **कांग्रेस का आरोप- शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा अब शराब पर ज्यादा पैसे वसूलेगी**

रायपुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने आज से प्रदेश में कई चीजों के दाम बढ़ने को लेकर भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर बीजेपी पर हमला करते हुए लिखा है कि प्रदेश की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

उन्होंने लिखा है कि- आज 1 अप्रैल है, यानि की अप्रैल फूल दिवस। आज लोगों को मूर्ख बनाने की परम्परा है। आज छत्तीसगढ़ की जनता भी खुद को भाजपा से ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज से छत्तीसगढ़ में जमीनो की रजिस्ट्री पर ज्यादा टेक्स देना होगा। शराबबंदी की बात करने वाली भाजपा की साय सरकार आज से शराब के दामों पर 150 रुपये ज्यादा वसूल करेगी। रेत के दाम भी तीन गुना ज्यादा हो गए हैं। राइस मिलरो से 40 रुपये नजराना वसूला जा रहा है। उफ ये अप्रैल फूल।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज से शराब की कीमतों में वृद्धि हो गई है। नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमत बढ़ाई गई है। प्रदेश में अब आज से क्वार्टर में 10 रुपये और बोतल में 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के सभी सेस हटाए और नई नीति के तहत

शराब की कीमतों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस नई नीति के अनुसार, शराब की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे गौठान के विकास, कोरोना के समय लगाए सभी टैक्स हटाए जाने और अधोसंरचना और विकास के लिए आवश्यक निवेश का कारण बताया गया है। नई नीति के अनुसार, शराब की बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो गई है। इसके अलावा आज से जमीन की रजिस्ट्री करने पर भी आपको ज्यादा टेक्स देना होगा। वहीं रेत के दाम भी बढ़े हैं।

दीपक बैज के ट्वीट पर डिप्टी सीएम साव का पलटवार

पीसीसी चीफ दीपक बैज के ट्वीट पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने 5 साल जनता को ठगा उन्हें ऐसी बातें कहने का अधिकार नहीं है। साय सरकार मोदी की हर एक गारंटी को पूरा कर रही है। प्रदेश की जनता के व्यापक हित में निर्णय लेकर

काम कर रही है। बता दें कि आज से प्रदेश में रेत, शराब समेत कई चीजों के दाम बढ़े हैं। साथ ही जमीन की रजिस्ट्री पर भी अब ज्यादा टैक्स देना होगा। इसे लेकर बैज ने बीजेपी पर निशाना साधा था।

दीपक बैज द्वारा कांग्रेस के खिलाफ बयान देने वालों को बृहस्पति की बी-टीम बताने पर साव ने कहा कि कांग्रेस को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। किसी को बी-टीम किसी को स्लीपर सेल बता रहे हैं। यह बताता है वरिष्ठ नेताओं को कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा। जो समझदार लोग हैं वे डूबती नैया से लगातार बाहर आ रहे हैं।

महतारी वंदन की दूसरी किश्त को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि बैंकिंग प्रक्रिया हम सभी को पता है। ईयर एंडिंग होता है। बहुत जल्द ही बहनों के खातों में महतारी वंदन की राशि आ जाएगी।

इधर केंद्रीय नेताओं के दौरे को लेकर साव ने कहा कि पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई है। अब केंद्रीय नेतृत्व के कार्यक्रम बनेंगे। जैसे-जैसे स्वीकृति मिलेगी केंद्रीय नेताओं का आगमन होगा। प्रदेश के नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं।

कांग्रेस और जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता समेत

2 हजार से अधिक लोगों ने थामा भाजपा का दामन

बिलासपुर। बिलासपुर लोकसभा में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में 2 हजार से अधिक लोगों ने भाजपा में प्रवेश लिया। वहीं बिलासपुर विधानसभा से साढ़े तीन सौ लोगों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ली। जिसमें कांग्रेस, जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री दयालदास बघेल, विधायक धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, धर्मजीत सिंह ने सभी लोगों को भाजपा का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई।

वहीं मीडिया से बातचीत करते डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबती हुई जहाज है। न कांग्रेस की विश्वनीयता बची है, न नेतृत्व है। इसलिए कांग्रेस तो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीरो में आउट होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक का रिकॉर्ड जीत बिलासपुर लोकसभा सीट मि होने वाली है। 1996 से लगातार हम इस सीट को जीतते रहे हैं। 2024 की जीत ऐतिहासिक होने वाली है और रिकॉर्ड वोटों से हमारे प्रत्याशी तोखन साहू जीतने वाले हैं।

प्रधानमंत्री मोदी 8 को बस्तर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित

रायपुर। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए छत्तीसगढ़ की एक सीट बस्तर पर वोटिंग होगी। इससे पहले प्रचार-प्रसार के लिए कई दिग्गज नेता यहां आने वाले हैं। मुख्यमंत्री साय बहुत दिनों से अलग-अलग जगहों पर जाकर सभाएं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहां पर आएंगे। पीएम मोदी 8 अप्रैल को बस्तर के दौरे पर आने वाले हैं। बस्तर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे।

बता दें, बस्तर में 19 अप्रैल को है लोकसभा चुनाव होना है। इसलिए भाजपा अपनी पूरी तैयारी पहले से कर रही है। इसके अलावा कई दिग्गज नेता जनता के बीच पहुंचकर 'मोदी की गारंटी' के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पहले चरण में एकमात्र सीट बस्तर में चुनाव होना है। बस्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कराने की तैयारी है। वहीं बताया जा रहा है कि 5 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा बस्तर में हो सकती है।

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन का छत्तीसगढ़ पर भी बड़ा फोकस है। भाजपा ने यहां की सभी 11 की 11 सीटें जीतने की रणनीति तैयार की है।

इसको लेकर प्रचार- प्रसार में भी पूरी ताकत झोंकने की रणनीति बनी है। चुनाव के लिए रणनीति बनाने का जिम्मा इस बार प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन पर है। उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि यहां पर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर का आना नहीं हो रहा है।

3 को आएगी महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त

रायपुर। महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त मिलने की तारीख सामने आ गई है। इस बार महिलाओं के खाते में 3 अप्रैल को पैसे आ जाएंगे। महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने इसकी जानकारी दी। लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत कर उन्होंने कहा कि जहां-जहां दिक्कत है, उसको दिखाकर तत्काल पैसे डाले जाएंगे। इस दौरान लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, एक लाख रुपये का फॉर्म भरवा रहे हैं। किस बेस पर एक लाख देंगे। कांग्रेस सिर्फ धोखा देना जानती है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि 3 अप्रैल को महिलाओं के खाते में महतारी वंदन योजना की दूसरी किस्त आएगी। पैसे डीबीटी के माध्यम से डाले जा रहे हैं। महिलाओं को जो हमने वादा किया था कि सालाना 12 हजार रुपये देंगे। प्रति माह के दर से 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। बहुत से महिलाओं के खाते में अब तक पैसे नहीं गए, जिसको लेकर मंत्री राजवाड़े ने कहा, अभी कुछ दिन पहले डायरेक्टर से बात हुई थी। इसमें उन्होंने कहा है कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं। कुछ ही परसेंट

महिलाएं बची हैं। ऐसे जो जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, उनको ऊपर से निर्देश दे दिया गया है कि जहां-जहां दिक्कत है उसको दिखाएं और तत्काल पैसा डाला जाए। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सभी महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी, जो पात्र हैं जिनकी सूची में नाम होगा, उनको मैं कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। सभी महिलाओं के खाते में 1000 जाएंगे। टेक्निकल इशू हो सकते हैं, लेकिन वह भी सही हो जाएंगे। पैसा निरंतर मिलते रहेगा।

लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा, तैयारी जोर-शोर से चल रही है। सभी फील्ड पर उतर चुके हैं। प्रत्याशी जगह-जगह जाकर अपना कार्यक्रम आयोजन करवा रहे हैं। वोट मांग रहे हैं और जनता का पूरा मूड बन चुका है। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। छत्तीसगढ़ में तीन चरण में चुनाव होने वाले हैं। तीनों चरण में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोग वोट देंगे और सरकार भी बनाएंगे। लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा, दोनों दल ने महिला प्रत्याशी के रूप में तीन-तीन प्रत्याशी उतारे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। ऐसे में पूर्ण विश्वास के साथ पूरी महिलाएं भाजपा को ही वोट देंगी। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो घोषणा पूरा नहीं कर पा रही थी। उनको उसका कामयाजा भी भुगतना पड़ेगा। केंद्र में फिर से नरेन्द्र मोदी की सरकार बन रही है। भाजपा के सभी प्रत्याशी जीत रहे हैं। एक-एक लाख रुपये देने को लेकर कांग्रेस की ओर से भरवाए जा रहे फॉर्म को लेकर मंत्री राजवाड़े ने कहा कि कभी एक भी घोषणा पूरा नहीं कर पाए। आज एक लाख रुपये का फॉर्म भरवा रहे हैं। किस बेस पर एक लाख देंगे। यह पहले कांग्रेसी बता दें। हमने जो वादा किया था, हम वह वादा पूरा किए हैं। कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस सिर्फ धोखा देना जानती है। बस उनका काम ही वही है।

गरियाबंद में हेलीकॉप्टर की हुई ट्रायल लैंडिंग

लोकसभा चुनाव में आसमान से भी होगी निगरानी

गरियाबंद। पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सियासी दलों के साथ ही प्रशासनिक टीम भी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इस बीच गरियाबंद में सोमवार को हेलीकॉप्टर की ट्रायल लैंडिंग की गई। ताकि आगामी चुनाव में संवेदनशील मतदान केन्द्रों तक मतदान दलों को पहुंचाया जा सके। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में चुनाव कराकर लौटते समय मतदान दल की सुरक्षा में तैनात जम्मू कश्मीर का जवान शहीद हो गया था। यही कारण है कि इस बार सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक टीम अलर्ट है।

दरअसल, गरियाबंद में सोमवार को लोकसभा चुनाव को लेकर हेलीकॉप्टर का ट्रायल लैंडिंग किया गया। 26 अप्रैल को यहां मतदान होने हैं। चुनाव को लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड में आ गया है। इस बारे में गरियाबंद की डीएसपी निशा सिन्हा ने जानकारी दी कि लोकसभा चुनाव

से पहले सभी तरह की परिस्थितियों से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। इसके तहत अगर जरूरत पड़ी तो कुछ मतदान केंद्रों तक मतदान दल को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए पहले से ट्रायल लैंडिंग कर स्थितियों का जायजा लिया गया है।

डीएसपी निशा सिन्हा ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर हर परिस्थितियों से निपटने की तैयारी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर कुछ मतदान केंद्रों तक मतदान दल को पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए पहले से ट्रायल लैंडिंग कर स्थितियों का जायजा लिया।

बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में बिंद्रानवगढ़ विधानसभा में चुनाव संपन्न कराकर लौटते समय मतदान दल की सुरक्षा में तैनात जम्मू कश्मीर का एक जवान शहीद हो गया था। यही वजह है कि इस बार प्रशासनिक टीम पहले से ही हर परिस्थिति से निपटने को लेकर अलर्ट है। साथ ही अंदरूनी क्षेत्रों में मतदान को लेकर टीम ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं।

आइकॉन सोलर-एन पावर टेक्नोलॉजीज को उभरती सोलर कंपनी के रूप में सम्मानित

रायपुर। आइकॉन सोलर-एन पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने सुशासन का जश्न मनाते हुए एक कार्यक्रम में एक अग्रणी मीडिया हाउस द्वारा सर्वश्रेष्ठ सोलर कंपनी के रूप में अपनी मान्यता की घोषणा की। सौर पैनल निर्माण में एक दशक लंबी विशेषज्ञता के साथ, आइकॉन सोलर मध्य भारत में सबसे बड़े निर्माता के रूप में खड़ा है। जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार का प्रतीक है।

आइकॉन सोलर का प्रभाव सीमाओं से परे है। इसके सौर पैनल न केवल भारत भर में बल्कि फिलीपींस, श्रीलंका, वियतनाम और कई अफ्रीकी देशों में भी परियोजनाओं को रोशन कर रहे हैं। रणनीतिक वितरक भागीदारी के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार में आसन्न विस्तार कंपनी के वैश्विक आउटरीच प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की बढ़ती मांग के बीच, आइकॉन सोलर उल्लेखनीय वृद्धि के लिए तैयार है, जैसा कि चालू वित्तीय वर्ष के भीतर तीन गुना विस्तार की घोषणा से पता चलता है।

यह विस्तार सौर उद्योग की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

छत्तीसगढ़ के लिए गौरव के प्रतीक के रूप में आइकॉन सोलर की उपलब्धियां इस क्षेत्र के नवीकरणीय ऊर्जा नवाचार के केंद्र के रूप में उभरने को दर्शाती हैं। यह सम्मान वैश्विक सौर परिदृश्य में अग्रणी के रूप में आइकॉन सोलर-एन पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की स्थिति की पुष्टि करता है, जो सभी के लिए एक स्वच्छ और उज्ज्वल भविष्य की दृष्टि को आगे बढ़ाता है।

कांग्रेस ने दी न्याय की 5 गारंटी, हर साल महिलाओं को मिलेगा 1 लाख रुपये

■ **सरकारी भर्ती में मिलेगा विशेष लाभ**

रायपुर। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों के ऐलान के बाद से सभी राजनीतिक पार्टियों में तैयारियां जोर-शोर से हो रही है। वहीं राजधानी रायपुर में स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज कांग्रेस ने पत्रकारवार्ता ली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए 5 न्याय की गारंटी लोगों दी गई है। कांग्रेस ने कहा कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपये मिलेगा। भाजपा सरकार महिलाओं को 1000 रुपये देती है, लेकिन कांग्रेस 8333 रुपये प्रति माह देगी। इसके अलावा केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा मजदूरों को 400 रुपये मजदूरी मिलेगी। वहीं एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाएगी।

पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों 5 न्याय की गारंटी दी है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला, युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए उनको कानूनी संरक्षण मिले। इसके लिए पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए किसान न्याय, युवा न्याय, नारी

न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है।

नारी न्याय में कांग्रेस महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना लागू करेगी

1. इसमें हर महिला को साल में एक लाख रुपये यानी महिने में 8333 रुपये मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महिने में मात्र 1000 रुपये यानी साल में 12,000 रुपये देगी। मगर कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी। 2. कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी। 3. आशावर्कर, आंगनबाड़ी और मिडडे मील कार्यकर्ताओं को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जाएगा। 4. महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 5. देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल बनाया जाएगा।

किसान न्याय में कांग्रेस किसानों के सुख-समृद्धि के लिए 5 गारंटी देती है

1. एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ। एमएस स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी। 2. किसानों के ऋण माफ करने और आवश्यक ऋण माफी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफी आयोग की स्थापना की जाएगी। 3. किसानों के फसलों के नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को फिर से डिजाइन किया जाएगा। 4. कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा। 5. किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छुट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा

युवा न्याय में कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिए युवाओं को 5 गारंटी देती है

1. भर्ती भरोसा- केन्द्र सरकार में कैलेंडर के नुसार 30 लाख नयी नौकरियां। 2. पहली नौकरी पक्की- प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रू (8500/ माह)। 3. पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिये एक नीति। 4. गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकॉनामी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन। 5. युवा रोशनी 5000 करोड़ रू का युवाओं के लिये स्टार्ट- अप कोष।

श्रमिक न्याय में कांग्रेस देश के श्रमिकों से वायदा करती है कि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिए मनरेगा कानून बनाया था और हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये करने की गारंटी देती है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आएगा।

1. स्वास्थ्य अधिकार- अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर। 2. श्रम का सम्मान- 400 रुपये प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा, श्रमिकों के लिए भी। 3. शहरी रोजगार गारंटी- शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम। 4. समाजिक सुरक्षा- असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा। 5. सुरक्षित रोजगार- कांट्रेक्ट सिस्टम सरकारी कार्यों में बंद होगा।

हिस्सेदारी न्याय

1. गिनती करो- व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना। 2. आरक्षण का हक- एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जाएगी। 3. एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप-बजट। 4. जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान। 5. अपनी धरती, अपना राज- जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे।

केजरीवाल की गिरफ्तारी का चुनाव पर असर

उमेश चतुर्वेदी

लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी हो, इसी बीच किसी राज्य के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी का दावा है कि इन गिरफ्तारियों के पीछे कोई राजनीति नहीं है। लेकिन राजनीति और लोक का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो इन गिरफ्तारियों के पीछे राजनीति देख रहा है। मोदी विरोधी आईएनडीआईए गठबंधन में चूंकि केजरीवाल भी शामिल हैं, लिहाजा गठबंधन के नेता इन गिरफ्तारियों को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बताने-बनाने में जुट गए हैं। उनका एक ही सवाल है कि आखिर सिर्फ विपक्षी नेताओं को ही ईडी या सीबीआई निशाना क्यों बना रहे हैं? बार-बार ऐसा कहकर एक तरह से मोदी विरोधी मोर्चे के नेताओं की कोशिश यह है कि इन गिरफ्तारियों को भ्रष्टाचार की बजाय सिर्फ राजनीति का रंग दिया जाए और इसके जरिए मोदी विरोधी वोटों की फसल काट ली जाये। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है? मोदी के उभार के बाद के दोनों संसदीय चुनावों में दिल्ली विधानसभा में अपार बहुमत रखने वाली आम आदमी पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई है। इस बार तो आम आदमी पार्टी ने उस कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है, जिसके भ्रष्टाचार के विरोध में उसका समूचा अस्तित्व पनपता रहा। दिल्ली में लोकसभा की सात सीटें हैं, जिनमें तीन सीटों पर जहां कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी चार सीटों पर मैदान में है। पिछले दो आम चुनावों में आम आदमी पार्टी की स्थिति तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। गठबंधन करके कांग्रेस और आम आदमी पार्टी-दोनों ने उम्मीद लगा रखी है कि दो आम चुनावों से जारी दिल्ली में उनका सूखा शायद कम हो जाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी के पहले तक ऐसा नहीं लग रहा था कि विगत के दो चुनावों से इतर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का इतिहास इस बार इतर होने जा रहा है। लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दोनों पार्टियों को सहानुभूति लहर उठने की उम्मीद है। उन्हें लगता है कि सहानुभूति की वजह से इस बार भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंध लग सकती है। शराब घोटाले में केजरीवाल के पहले उनके दो स्तंभों पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी जमानत की याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाले में दिल्ली से तीसरी बड़ी गिरफ्तारी केजरीवाल की हुई है। इसी केस में भारत राष्ट्र समिति की नेता और पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी गिरफ्तार हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार करने से पहले ईडी ने नौ बार समन देकर उन्हें बुलाया। लेकिन हर बार वे ईडी के सामने जाने से बचते रहे। केजरीवाल का राजनीतिक अनुभव भले ही कम हो, लेकिन उनकी पैंतरेबाजी से साफ है कि राजनीति करने में वे पुराने से पुराने नेताओं पर भारी हैं। समन को अनदेखा करके एक तरह से वे इस मुद्दे को जिंदा रखने और इसके जरिए अपने लिए वोटरों की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते रहे। गिरफ्तारी के बावजूद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ना देकर भी केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। ईडी की हिरासत से ही वे दिल्ली के लिए दो आदेश जारी कर चुके हैं। पहले में जहां उन्होंने दिल्ली की सीवर व्यवस्था दुरूस्त करने का आदेश दिया है, वहीं उनका दूसरा आदेश स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखना है। दिल्ली में विपक्षी भूमिका निभा रही भारतीय जनता पार्टी इस पर हंगामा कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से केजरीवाल को हटाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई। जिसे हाईकोर्ट ठुकरा चुका है। इसके बावजूद नैतिकता के आधार पर भाजपा केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन केजरीवाल के खेमे के तर्क है कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अपने पद से इस्तीफा दे ही देना होगा। इस तर्क के सहारे केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पर जमे हुए हैं। हिरासत से आदेश देना और उसका आम आदमी पार्टी द्वारा भरपूर प्रचार किया जाना दरअसल केजरीवाल के प्रति सहानुभूति हासिल करने की प्रक्रिया का ही विस्तार है।

टैक्स की चोरी, ऊपर से सीनाजोरी?

स्वाति

चुनाव के दिनों में लोकतांत्रिक हथियार के रूप में आरोप प्रत्यारोप का खेल खूब देखा जाता रहा है, मगर फाइनेंसियल टूल को चुनाव लड़ने का हथियार बना लेना यह 2024 के लोकसभा चुनाव को सबसे अलग बना रहा है। इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट का विपक्षी दलों को नोटिस भेजना भले एक रूटीन काम हो सकता है, मगर इसकी टाइमिंग विपक्ष को सत्तारूढ़ दल पर हमला करने का मौका जरूर दे रही है। वैसे देखा जाए तो पहले भी सत्तासीन पार्टियों द्वारा ऐसी संस्थाओं के उपयोग की कहानी न्यायालयों द्वारा भी दुरुपयोग के विशेषण से नवाज़ी गई है परन्तु अबकी यह मामला प्रभाव क्षेत्र के हिसाब से बहुत आगे निकल गया है।

इन्कम टैक्स का नोटिस सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के लिए अस्तित्व का संकट लेकर आया है। शनिवार को ज़ारी किये गए डिमांड नोटिस के बाद कांग्रेस पर आयकर विभाग का कुल लगभग 3,567 करोड़ रूपये बकाया बैठता है। ताजा डिमांड नोटिस 1745 करोड़ रूपये का है जो वित्त वर्ष 2014- 2015, 2015- 2016 और 2016- 2017 का है। हालांकि इसकी आशंका कांग्रेस शुक्रवार की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर कर चुकी थी कि उसे अभी और परेशान किया जाएगा। इसके पहले जो कांग्रेस को नोटिस मिला था वह 1823 करोड़ रूपये का था। यह बकाया पांच अलग-अलग वित्तीय वर्षों के लिए था और इसमें मूल और ब्याज दोनों राशियां शामिल है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस नोटिस में वित्तीय वर्ष 1994-1995 में कांग्रेस पार्टी द्वारा वित्तीय गड़बड़ी और टैक्स की हेरा फेरी का वित्तीय दंड भी शामिल है।

आयकर विभाग के ये नोटिस कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर इसलिए खड़े हो गए हैं क्योंकि पार्टी ने 2023-2024 के आयकर रिटर्न में पार्टी की कुल संपत्ति ही 1430 करोड़ रूपये बतायी थी। इसमें 657 करोड़ रूपये का फंड, 340 करोड़ की चल अचल संपत्ति और लगभग 388 करोड़ का लिक्विड कैश बताया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि पार्टी अपनी कुल संपत्ति बेचकर भी आयकर विभाग का फाइन नहीं भर सकती।

अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस पार्टी दिवालिया घोषित हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो यह भारतीय राजनीति की एक ऐसा घटना होगी जो अगर सकारात्मक प्रभाव को लेकर आगे बढ़ी तो कभी भी कोई पोलिटिकल पार्टी इन्कम टैक्स के नियमों को सुविधानुसार उपयोग में लाने की भूल से बचेगी। लेकिन अगर इसी को नकारात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाने लगा तो %बदले की भावना% से ग्रसित होकर स्वयं सत्ता में आने पर पूर्वकालिक सत्तारूढ़ पार्टियों के ऊपर भी ऐसी ही कार्यवाही करेगी। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की %धमकी% दे चुके हैं।

अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस और समस्त इंडिया गठबंधन आयकर विभाग के नोटिस को जिस तरह से गलत बता रहा है वो नोटिस सही हैं या गलत? शनिवार को जारी 1745 करोड़ रूपये के नोटिस के अलावा दूसरा मामला 1700 करोड़ के नोटिस का है। मामला 2017 से 2021 के बीच कांग्रेस को कैश के रूप में मिले चंदे और अन्य कैश अनियमितताओं से जुड़ा है। इसमें लगभग 526 करोड़ रूपये शामिल हैं, जिसका स्पष्ट हिसाब-किताब कांग्रेस के पास नहीं है।

दरअसल 2019 में आयकर विभाग के कई छापों के दौरान यह बात खुल कर सामने आई थी कि दो कंपनियां %मेधा इंजीनियरिंग% और कमलनाथ के करीबी की एक कम्पनी ने कैश में कांग्रेस को ये पैसे दिए हैं। आयकर विभाग को इन कंपनियों द्वारा कांग्रेस को ट्रांजेक्शन की रसीद मिली है। सूत्रों के अनुसार 20 करोड़ के एक पेमेंट का ब्यौरा आयकर विभाग के पास ऐसा भी है जिसमें कमलनाथ के जरिये पैसा सीधे कांग्रेस ऑफिस को गया है। आयकर विभाग दावा कर रहा है कि ये सारे पैसे रिश्वत के हैं जिसे मध्य प्रदेश में मंत्रियों और अफसरों को दिया गया था और जो घूम फिर कर कांग्रेस पार्टी को फंड के रूप में मिला है। यह आयकर कानून के सेक्शन 13( ) का उल्लंघन है जिसके अनुसार 2,000 रूपये से ज्यादा कैश पेमेंट कोई पार्टी नहीं ले सकती।

इसी तरह तीसरा मामला 135 करोड़ का है। यह 2018- 2019 के बीच का है। इस दौरान कांग्रेस ने साढ़े 14 लाख रुपये का दान नकद में लिया और टैक्स रिटर्न भी 33 दिन की देरी से फाइल किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि उस वित्त वर्ष में कांग्रेस की कुल आय को ही टैक्स रिबेट के दायरे से बाहर कर दिया गया जो 135 करोड़ था। राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में छूट आयकर कानून की धारा 13(1) के तहत क्लेम करनी पड़ती है। कांग्रेस पर इसी प्रावधान के उल्लंघन का आरोप है।

चूंकि पार्टी ने इस वित्त वर्ष के दौरान 33 दिन की देरी से टैक्स रिटर्न फाइल किया तो आयकर विभाग ने कांग्रेस की कुल 199 करोड़ की आय पर टैक्स के छूट के दावे को खारिज कर दिया। हालांकि 2021 में विभाग ने 105 करोड़ की अनियमितता के एवज में नियमानुसार 20 फीसदी यानी 21 करोड़ चुकाने को कहा था जिसके बाद केस की सुनवाई तक स्टे लग जाता। पर कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। परिणामस्वरूप 16 मार्च को आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों से 135 करोड़ रुपये की वसूली कर ली। इसमें से 103 करोड़ के करीब का जुर्माना था और बाकी के 21 करोड़ इस जुर्माने पर लगे ब्याज की रकम थी। यह अमाउंट %लियन% है अर्थात बैंक अकॉउंट में फाइन वाली अमाउंट पर रोक लगा दी गई है, बाकी पैसों को पार्टी खर्च कर सकती है। यहीं कांग्रेस झूठ का भ्रम फैला रही है कि उसके बैंक अकॉउंट %फ्रीज% कर दिये गये हैं। मगर वास्तव में ऐसा है नहीं। अब इनके अकॉउंट में सिर्फ फाइन जितने पैसे थे तो क्या ही किया जा सकता है और अब तो कुल फाइन जितने पैसे भी कांग्रेस के एकाउण्ट में नहीं बचे हैं।

चौथा मामला 1994-95 की आय और उससे जुड़े हिसाब-किताब की गड़बड़ी से है। इस केस में आयकर विभाग ने पार्टी पर 53 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यहां भी आयकर कानून की धारा 13 के सेक्शन ए के उल्लंघन की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अलावा तृणमूल कांग्रेस को भी आयकर विभाग का नोटिस मिला है। इसके अलावा सीपीआई को भी 11 करोड़ का नोटिस विभाग ने भेजा है। पार्टियां अगर चाहती तो इन सारे नोटिस में फाइन अमाउंट का 20त्न जमा कर नोटिस के विरुद्ध क्लेम में जा सकती थी। इससे बैंक के भी लेन देन में रोक नहीं लगती, ना ही कोई अमाउंट रोका जाता। लेकिन ऐसा करने के बजाय कांग्रेस अदालत के दरवाजे पर पहुंच गयी। दिल्ली उच्च न्यायालय कांग्रेस पार्टी के नोटिस पर स्टे की गुहार को ख़ारिज कर चुका है। आयकर ट्रिब्यूनल ने भी मामले में पुन: अवलोकन से इन्कार कर दिया है। अब कांग्रेस चाहे कितनी भी दुहाई दे कि पुराने मामलों को %री-इन्वेस्टीगेट% कर भाजपा गलत कर रही या ऐसे ही अनियमितता भाजपा ने भी बरती है तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं?

ये राजनीतिक सवाल हैं परंतु सच यही है कि पैसे के लेन देन में कांग्रेस पार्टी ने नियमों को ताख पर रखा है। जब सामान्य तरीके से वो अपनी छूट का लाभ ले सकते थे तब भी उनकी ओर से अनदेखी की गयी। अब कानून के अनुसार आयकर विभाग कार्रवाई कर रहा है तो कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियां इसे राजनीतिक रंग दे रही हैं। यह चोरी के बाद सीनाजोरी वाली कहावत को चरितार्थ करने जैसा है। बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट में आयकर विभाग ने आज सूचित किया है कि वह जुलाई तक कांग्रेस के खिलाफ किसी प्रकार की जब्ती या वसूली की कार्रवाई नहीं करेगा क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। जुलाई में आयकर विभाग क्या करेगा या फिर कांग्रेस क्या करती है, यह उस समय पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस के सामने जो टैक्स संकट खड़ा हुआ है वह उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है। इसका केन्द्र सरकार पर दोषारोपण उचित नहीं होगा।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-44)

गतांक से आगे...

संसार में मात्र आस्था (आशा) ही अनेक कष्टों की उत्पत्ति का कारण है और अनास्था (आशा-अपेक्षारहित जीवन) ही सुख का घर समझना चाहिए। वासनाओं के सूत्र से बँधा हुआ यह संसार पुन: पुन: उत्पन्न होता है। वह प्रख्यात वासना अति कष्टदायिनी बनकर समस्त सुखों का पूरी तरह से उच्छेदन करने के लिए आती है। जंजीर से सिंह के बाँधने के समान वासना के मोहपाश में धीर, कुलीन, अति बहुश्रुत तथा महान् व्यक्ति भी बँध जाते हैं। शास्त्रानुकूल आचरण करता हुआ, परम पुरुषार्थ का अवलम्बन लेकर और श्रेष्ठ उद्यम करते हुए कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं करता?

मैं समस्त विश्वरूप हूँ, मैं अच्युत परमात्मस्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं इस तरह के बोधात्मक अहंभाव को उत्तम माना गया है। मैं सभी प्रपञ्च से भिन्न हूँ, मैं बाल के अग्रभाग से कहीं अधिक सूक्ष्म हूँ-इस प्रकार का दूसरा अहं भाव मोक्ष को देने वाला है, बन्धन में फँसाने वाला नहीं। जीवन्मुक्त आत्मायें ही ऐसे अहंभाव से युक्त होती हैं।

मैं हाथ-पैर वाला मात्र स्थूल शरीरधारी हूँ इस प्रकार की मान्यता जो तीसरे लौकिक अहंकार में होती है, उसे अत्यन्त निकृष्ट कहा गया है। अहंकार से युक्त दुरात्मा प्राणी ही कष्टमय संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है। इससे प्रताड़ित प्राणी निरन्तर पतन की ओर बढ़ता है। इस तृतीय दु:खमय अहंभाव का परित्याग करके लम्बे समय से शुभ अहंभाव में संलग्न प्राणी शान्तचित्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं।

प्रारम्भिक दो अलौकिक अहंकारों को स्वीकार करके तीसरे दु:खप्रद लौकिक अहंकार को त्याग दे। साधन शक्ति की वृद्धि पर इन सब प्रकार के अहंकारों को त्यागकर निरहंकारिता ग्रहण करे, उसी से उत्तमपद की प्राप्ति सम्भव है।

क्रमश: ...

विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस

विकास

विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा मनाया जाता है। दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में अपने नागरिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा ऑटिस्टिक सेल्फ एडवोकेसी नेटवर्क, ग्लोबल ऑटिज्म प्रोजेक्ट और स्पेशलिस्टर्न फाउंडेशन सहित नागरिक समाज भागीदारों के समर्थन से किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव (ए/आरईएस/62/139) नामित किया। परिषद ने 1 नवंबर, 2007 को 'विश्व आत्मकेंद्रित जागरूकता दिवस' पारित किया और इसे 18 दिसंबर, 2007 को अपनाया। इसका उद्देश्य ऑटिस्टिक लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना था। पहला विश्व आत्मकेंद्रित दिवस वर्ष 2008 में 2 अप्रैल को मनाया गया था। विश्व आत्मकेंद्रित दिवस केवल सात आधिकारिक स्वास्थ्य-विशिष्ट संयुक्त राष्ट्र दिवसों में से एक है।

ऑटिज़्म, या ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सामाजिक कौशल, दोहराव वाले व्यवहार, भाषण और अशाब्दिक संचार के साथ चुनौतियों की विशेषता वाली स्थितियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। ऑटिज्म एक विकास विकार है। विकार को सामाजिक संपर्क और संचार के साथ कठिनाइयों की विशेषता है जिसमें प्रतिबंधित और दोहराव वाला व्यवहार भी शामिल हो सकता है। ऑटिज्म के लक्षण अक्सर पहले तीन वर्षों के दौरान बच्चे के माता-पिता द्वारा देखे जाते हैं। ये लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं।

ऑटिज्म के विकार को दूर किया जा सकता है। इसके लिए माता-पिता समेत लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। हालांकि, महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक होता है। इसके अलावा, बच्चे ऑटिज्म के अधिक शिकार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रयास सरहनीय है। इससे ऑटिज्म को जड़ से खत्म किया जा सकता है।

ऑटिज़्म का प्रभाव- ऑटिज़्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2010 तक विश्व में तकरीबन 7 करोड़ लोग ऑटिज्म से प्रभावित थे। इतना ही नहीं दुनियाभर में ऑटिज़्म प्रभावित रोगियों की संख्या मधुमेह, कैंसर और एड्स के रोगियों की संख्या मिलाकर भी इससे अधिक है। ऑटिज़्म प्रभावित रोगियों में डाउन सिंड्रोम की संख्या अपेक्षा से भी अधिक है। ऑटिज़्म पीड़ितों की संख्या का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनियाभर में प्रति दस हज़ार में से 20 व्यक्ति इस रोग से प्रभावित होते हैं।

आखिर न्यायपालिका को कौन धमकी दे रहा है?

शेखर गुप्ता

देश की उच्च न्यायपालिका के इर्दगिर्द पिछले कुछ समय में कई घटनाएं घटी हैं। पहले हरीश साल्वे सहित 'बार' के 600 सदस्यों ने देश के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिख कर उच्चतम न्यायालय के साथ ऐसे समय में एकजुटता और समर्थन दर्शाया जब उनके मुताबिक उस पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। इसे 'बार' में आम तौर पर होने वाली राजनीति माना जा सकता है, खासकर यह देखते हुए कि पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में बार काउंसिल के चुनाव भी पार्टियों के चुनाव चिह्न पर लड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवक्ताओं के समर्थन और एकजुटता के पत्र को एक दिलचस्प टिप्पणी के साथ साझा किया- 50 वर्ष पहले कांग्रेस ने एक 'प्रतिबद्ध न्यायपालिका' की मांग की थी। यह बात हमें 1973 और 1977 में ले जाती है जब इंदिरा गांधी की सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति की मान्य परंपरा का दो बार उल्लंघन किया था। दोनों बार यह निर्णय राजनीति से प्रेरित था। वास्तव में दोनों ही नियुक्तियां उस दशक में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अहम निर्णयों से जुड़ी थीं।

पहली बार अप्रैल 1973 में तीन वरिष्ठतम न्यायाधीशों जयशंकर मणिलाल शेलत, एएन ग्रोवर और केएस हेगड़े की अनदेखी करके अजित नाथ राय को मुख्य न्यायाधीश चुना गया। जिन तीन न्यायाधीशों की अनदेखी की गयी थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यह मामला केशवानंद भारती मामले से जुड़ा हुआ था जिसमें 13 न्यायाधीशों के पीठ ने 7-6 से यह निर्णय दिया था कि कुछ ऐसा है जिसे भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा कहा जाता है। राय उन छह न्यायाधीशों में शामिल थे जिन्होंने कहा था कि ऐसा कोई ढांचा नहीं है। जिन तीन न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी की गई वे 'बुनियादी ढांचे' के सिद्धांत के हिमायती थे और हम भारतीय उनके ऋणी हैं। दूसरी बार ऐसा मौका जनवरी 1977 में आया जब कुछ ही समय बाद आपातकाल को हटाया जाने वाला था। इंदिरा गांधी अपने लिए सबसे अधिक असहज स्थिति पैदा करने वाले न्यायाधीश को दंडित करना चाहती थीं। इस बार एच आर खन्ना की वरिष्ठता की अनदेखी करके एम एच बेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। खन्ना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1973 की घटना के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि क्या होने वाला है। वह उन सात लोगों में से एक थे जिन्होंने केशवानंद भारती में बहुमत से बुनियादी ढांचे के पक्ष में निर्णय दिया था। इससे भी अहम बात है कि आपातकाल के दौरान बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले जिसे एडीएम जबलपुर मामले के नाम से जाना जाता है, उस मामले में जहां पांच में से चार न्यायाधीशों ने सरकार के नागरिक अधिकारों में कटौती के नजरिये का समर्थन किया था, वहां भी खन्ना इकलौते असहमत न्यायाधीश थे। खन्ना कभी देश के मुख्य न्यायाधीश नहीं बने लेकिन वह देश के न्यायाधीशों में बहुत बड़े कद के न्यायाधीश माने जाते हैं। इंदिरा गांधी का सत्ता प्रतिष्ठान न्यायाधीशों को अपनी समाजवादी धारा के प्रतिकूल मानता था, जिसे मतदाताओं का समर्थन हासिल था। उनके करीबियों में सोवियत झुकाव वाले वामपंथियों का प्रभाव था। यही वजह है कि भारत को ऐसे न्यायाधीशों की जरूरत थी जो इस बात की बेहतर समझ रखते कि जनता की इच्छा क्या है। इस लिहाज से उन न्यायाधीशों को निर्वाचित सरकार के लोकप्रिय रुख को लेकर 'प्रतिबद्ध' होना था। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में शामिल रहे प्रख्यात वामपंथी मोहन कुमार मंगलम को प्रतिबद्ध न्यायपालिका का विचार सामने रखने का श्रेय दिया जाता है।

तानाशाहों की चाह यह होती है कि संस्थाएं उनके हिसाब से 'एकदम दुरुस्त' हों क्योंकि उन्हें लगता है कि केवल वे ही संस्थाओं का निर्माण और उनकी रक्षा कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ने न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी करके न्यायपालिका को भी ऐसी ही संस्था में बदलना चाहा। प्रधानमंत्री मोदी 1973 में शुरू हुए उसी चलन का जिक्र कर रहे थे। ऐसे में यह सवाल आएगा कि आखिर आज ऐसा कौन है जो न्यायपालिका का दमन करने का प्रयास कर रहा है? यकीनन प्रधानमंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक ऐसा करने वाली कांग्रेस है। अगर वाकई ऐसा है तो कहा जा सकता है कि लोक सभा में 52 सीट वाली कांग्रेस अपनी क्षमता से कई गुना अधिक ताकत का प्रदर्शन कर रही है। एक लोकतंत्र में हर प्रकार की कमी से रहित 'संपूर्ण संस्थान' जैसा कुछ नहीं होता। भारतीय न्यायपालिका भी इससे कोसों दूर है लेकिन सवाल यह है कि क्या हाल के दिनों में वह पहले की तुलना में अधिक अपूर्ण स्थिति में है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लिए हाल के दिनों का अर्थ क्या है। यह इससे भी तय होगा कि आपकी राजनीति क्या है।

उदाहरण के लिए अगर आप मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी पक्ष के हैं तो आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2010 से 2014 के बीच घोटालों के दौर में अपना रास्ता खो दिया था। उस दौर में न्यायाधीश तमाम आदेश जारी कर रहे थे जिनमें से कुछ मौखिक हुआ करते थे। वे सभी प्रभावी आरोपियों को दोषी करार दे रहे थे और दूरसंचार क्षेत्र के '2जी जैसे घोटालों' की सीधी निगरानी कर रहे थे। उनकी बातों में गुस्सा जाहिर था। वर्तमान राजनीति की परवाह नहीं करने वाले और क्रिकेट के प्रति पूर्वग्रह रखने वाले व्यक्ति के रूप में मैं सोच सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय उस वक्त रास्ते से भटक गया जब उसने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का संचालन अपने हाथ में लेते हुए भारतीय क्रिकेट का प्रबंधन करने की ठानी। इससे भारतीय क्रिकेट का कुछ भी भला नहीं हुआ लेकिन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, अफसरशाहों और सेना के तीन सितारा अधिकारियों को जरूर मालामाल किया।

अगर भाजपा के साथ हैं या आप भाजपा से हैं तो आपके लिए 'हाल के दिनों' का अर्थ क्या होगा? इस पत्र और प्रधानमंत्री के बयान को देखें तो लगेगा कि वह वक्त अभी है। क्या यह बेनामी चुनावी बॉन्ड पर हुए निर्णय की वजह से है? वह उकसावे का एक बिंदु हो सकता है, हालांकि इन बॉन्ड से सामने आने वाली जानकारी एकतरफा नहीं है। हर किसी को इनसे लाभ हुआ और गोपनीयता बनाए रखने में सभी शामिल थे। हालांकि इसने कुछ अहम मुद्दे उभारे। मसलन सरकारी एजेंसियों के छापों और नियामकों के कदमों तथा कंपनियों के भुगतान के समय में क्या संबंध था। अधिवक्ताओं के पत्र को सावधानी से पढ़कर कुछ बिंदु तय किए जा सकते हैं कि आखिर इसे लिखने की वजह क्या होगी। इसे बचाव की कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह तब सामने आया जब चुनाव प्रचार आरंभ ही हुआ है। इसे सत्तातंत्र का जबरदस्त समर्थन मिला। पत्र में न्यायपालिका के बेनामी शत्रुओं का उल्लेख किया गया और कहा गया कि अदालती पीठ को 'फिक्स' किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि दिन में अदालती बहस में और रात को समाचार चैनलों पर बहस के जरिये माहौल बनाने और चुनिंदा न्यायाधीशों और फैसलों की आलोचना का आरोप लगाया गया। पत्र में एक वाक्य खासतौर पर दिलचस्प और रहस्य से भरा है। वह उन अधिवक्ताओं के बारे में है जो लोगों की राजनीतिक आलोचना करते हैं लेकिन अदालत में उनके बचाव के लिए खड़े होते हैं।

आज का इतिहास

1792 सिक्का कानून पारित कर दिया गया, संयुक्त राज्य मिंट की स्थापना हुई।
1801 वाइस एडमिरलहोरियो नेल्सन के नेतृत्व में दूसरे गठबंधन-ब्रिटिश सेनाओं के युद्ध ने कोपेनहेगन के युद्ध में डानो-नॉर्वेजियन बेड़े को हराया।
1801 कोपेनहेगन (द्वितीय गठबंधन युद्ध) की पहली लड़ाई- एडमिरल सर हाइड पार्कर के तहत यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी शाही डैनो-नार्वे नेवी को एक युद्धविराम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। वाइस-एडमिरल होरेटियो नेल्सन मुख्य हमले की ओर अग्रसर हुआ और उसने जानबूझकर अपने कमांडर को सेना वापस लेने का निर्देश दिया।
1860 ट्यूरिन में पहली इटली की संसद की बैठक शुरू हुई।
1865 अमेरिकी गृहयुद्ध तीसरी कोशिश में, केंद्रीय सेना बलों ने पीटर्सबर्ग, वर्जीनिया पर कब्जा कर लिया, हालांकि कॉन्फेडरेट के सरकारी अधिकारी और शेष अधिकांश कन्फेडरेट सेना भागने में सफल रहे।
1870 कार्डिफ़ जाइंट (माना जाता है कि पालतू मानव) जिप्सम साबित हुआ।
1902 पहला इलेक्ट्रिक फिल्म थियेटर, अमेरिका के लॉस एंजिल्स में खोला गया।
1911 ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो ने देश की पहली राष्ट्रीय जनगणना की।
1912 टाइटैनिक जहाज का समुद्री परीक्षण की शुरुआत हुई।
1935 ग्रेट ब्रिटेन के रॉबर्ट वॉटसन-वाट ने पहली व्यावहारिक रडार प्रणाली का तैयार किया।
1940 ब्रिटेन और डेनमार्क ने एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1941 जर्मन और इतालवी सेना ने अंग्रेजों को अजदबिया शहर से बाहर का रास्ता दिखाया।
1942 कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज किया।
1973 1967 में ओहियो स्टेट बार द्वारा आयोजित एक प्रयोग की निरंतरता के आधार पर लेक्सिस कंप्यूटर-सहायक कानूनी अनुसंधान सेवा शुरू की गई।
1973 लिबरल मूवमेंट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में लिबरल और कंट्रीलेग से अलग हो गया।
1982 अर्जेंटीना के विशेष बलों ने फ़ॉकलैंड द्वीप पर आक्रमण किया, जिससे फ़ॉकलैंड युद्ध छिड़ गया।

पंजाब को लेकर क्या है भाजपा की रणनीति?

समीर चौगांवकर

2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत से भारतीय जनता पार्टी डर गई थी और आप को अपने लिए एक चुनौती के रूप में देखने के लिए विवश हो गई थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में हार के बाद केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछा गया कि पंजाब में भाजपा की रणनीति क्यों फेल हुई तो अमित शाह ने कहा था कि पंजाब में हमारे पास अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। समय आने पर उनका इस्तेमाल करेंगे। उस समय मीडिया अमित शाह के बयान का अर्थ नहीं निकाल सका लेकिन अमित शाह जिस विकल्प की बात कर रहे थे वह यही था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तोड़ो। अमित शाह की रणनीति साफ है, अपनी लकीर बड़ी नहीं कर सकते तो विरोधियों की लकीर छोटी कर दो।

इसलिए भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कांग्रेस और आप पार्टी की लकीर छोटी करने में जुटी है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी आज अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं, आप के बड़े नेता संजय सिंह भी जेल में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद?केजरीवाल को 24 घंटे पहले ही ईडी की कस्टडी में दूसरी बार 4 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। आम आदमी पार्टी में आए इस भूचाल ने पंजाब में आप की जड़ों को हिला दिया है। जालंधर उपचुनाव में जीत कर पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद बने रिंकू और विधायक शीतल अंगुराल ने आप को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उधर पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और लुधियाना से दो बार के सांसद रवनीत बिट्टू ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परणीत कौर जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर पटियाला से चुनाव जीता था, वह भी भाजपा की सदस्य बन गई हैं। ऐसे में पंजाब में उम्मीदवारों के अकाल से गुजर रही भाजपा ने कांग्रेस और आप के नेताओं को तोड़कर पंजाब की 13 मे से 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। कांग्रेस से आने वाले बिट्टू को लुधियाना, परनीत कौर को पटियाला, रिं?कू को जालंधर सीट से टिकट मिलना तय है। भाजपा ने 2019 में पंजाब की दो सीटों गुरूदासपुर और होशियारपुर से जीत दर्ज की थी। इस बार भी होशियारपुर से सोमप्रकाश को टिकट मिलना तय है। गुरूदासपुर से भारतीय जनता पार्टी सनी देओल की जगह किसी और को टिकट देने पर विचार कर रही है। असल में भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर पंजाब दो कारणों से है। भाजपा का पंजाब में कोई जमीनी आधार नहीं है। ऐसे में उसके पास दूसरों दलों के नेताओं को अपने पाले में लाकर अपनी स्थिति को मजबूत करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। किसान आंदोलन के चलते पंजाब में भाजपा को फिलहाल कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा है। पंजाब को टारगेट पर लेने की दूसरी बड़ी वजह आप पार्टी और कांग्रेस का मजबूत आधार है।

2019 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 सीटों में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 2022 के विधानसभा चुनाव में 117 विधानसभा सीटों में से 92 सीटे आप पार्टी ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मालूम है कि 2019 में कांग्रेस की 52 सीटों में पंजाब की 8 और केरल की 15 सीटों का योगदान था। इन दो राज्यों से ही कांग्रेस को 23 सीटें मिली थी। ऐसे में पंजाब में कांग्रेस के कमजोर होने से लोकसभा में भी कांग्रेस कमजोर होगी। इधर आप पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में पब्लिक

सेंटिमेंट अगर कुछ हद तक आप के पक्ष में गया तो भाजपा को एक सीट का नुकसान दिल्ली में हो सकता है। पंजाब में आप पार्टी सभी 13 सीटें जीतने की स्थिति में है। पहले ही दिल्ली से 3 और पंजाब से 7 राज्यसभा सांसद आप पार्टी के हैं। ऐसे में पंजाब में यदि आप पार्टी 13 की 13 लोकसभा सीट जीत जाती है तो लोकसभा में 13 सांसद और राज्यसभा में 10 सांसद हो जाएंगे। इससे आम आदमी पार्टी का संसद में महत्व बढ़ जाएगा। भाजपा संसद की इसी स्थिति से बचना चाहती है और लोकसभा में आप की राह रोकने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

दरअसल, भाजपा पंजाब में अब दूसरे दलों के नेताओं को अपने पाले में लाकर पंजाब में अपनी स्थिति सुधारना चाहती है। पंजाब में अकाली दल और भाजपा का गठबंधन बहुत पुराना था। गठबंधन में हुए समझौते के तहत भाजपा 3 सीटों पर और अकाली दल 10 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। किसान आंदोलन के कारण अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को उम्मीद थी कि कांग्रेस से अलग हुए पंजाब के दिग्गज नेता अमरिंदर सिंह के साथ गठबंधन करने से उसे फायदा होगा लेकिन अमरिंदर किसी भी तरीके से भाजपा की कोई मदद नहीं कर सके। खुद भी विधानसभा चुनाव हारे और भाजपा के विधायकों की संख्या 2 से आगे नहीं बढ़ सकी। इसलिए अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद से भाजपा पंजाब में अपने लिए जमीन तलाश रही थी। यह जमीन उसे आप पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में नजर आयी है।

दिल्ली के बाद आप का आधार कहीं बढ़ा है तो वह पंजाब राज्य में है। 2014 के आम चुनाव में पंजाब से आप पार्टी के चार सांसद जीते थे। भगवंत मान संगरूर से, धर्मवीर गांधी पटियाला से, साधु सिंह फरीदकोट से और हरिंदर सिंह खालसा फतेहगढ़ साहिब से जीते थे। लेकिन 2019 में सिर्फ भगवत मान संगरूर से जीते थे। 2022 में मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवत मान ने संगरूर से इस्तीफा दे दिया था और उपचुनाव में आप को हार का सामना करना पड़ा था लेकिन विधानसभा चुनाव परिणामों ने आप को पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीतने की स्थिति में ला दिया। यही कारण था कि आप ने दिल्ली में तो कांग्रेस से गठबंधन किया लेकिन पंजाब में अकेले लड़ने का फैसला किया। लेकिन पंजाब में आप के सामने दोहरी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी आप में सेंध लगा रही है और कांग्रेस हर हाल में अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी को पंजाब में कांग्रेस के साथ साथ भाजपा से भी दो-दो हाथ करने पड़ रहे हैं।

केजरीवाल के जेल में होने के कारण पंजाब की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भगवंत मान के कंधों पर है। भाजपा का पिछला प्रदर्शन बताता है कि पार्टी अपने दम पर कुछ खास करने की स्थिति में नहीं है, इस कारण तोड़फोड़ कर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। भाजपा और अकाली गठबंधन टूटने के बाद 2022 संगरूर उपचुनाव में भाजपा को 9.33 प्रतिशत और अकाली को 6.25 प्रतिशत वोट मिले थे। भाजपा चौथे ओर अकाली दल पांचवे नंबर पर था। इसके बाद 2023 में जालंधर उपचुनाव में अकाली दल को 17.85 प्रतिशत और भाजपा को 15.19 प्रतिशत वोट मिले थे। अकाली तीसरे और भाजपा चौथे नंबर पर थी। आज तक पंजाब में?भाजपा का वोट शेयर दहाई के आंकड़े में नहीं पहुंच सका है। अब केजरीवाल की गिरफ्तारी का पूरा फायदा भाजपा पंजाब में उठाना चाहती है। पंजाब में आप को तोड़कर पार्टी का पूरे देश में मनोबल तोड़ना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल के ईडी कस्टडी में होने और उसके बाद जेल जाने की पूरी संभावना के बाद पार्टी का मनोबल पहले से टूटा हुआ है। भाजपा बस उसको थोड़ा सा ओर मरोड़ना चाहती है। इसमें भाजपा कितनी सफल होती है या आम आदमी पार्टी अपने आप को कितना संभाल पाती है यह चुनाव परिणाम बतायेगा।

आप के उभरते सितारे भगवंत मान पर निगाहें

हरीश गुप्ता

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे जाने के बाद सबकी निगाहें पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर टिकी हैं। हालांकि निकट भविष्य में कोई अस्थिरता देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जानकार सूत्रों का कहना है कि केजरीवाल की पत्नी के लिए मुख्यमंत्री पद या पार्टी के कार्यवाहक संयोजक की कमान संभालना आसान नहीं होगा। चूंकि शराब नीति घोटाले में किसी भी नेता; मनीष सिसोदिया या संजय सिंह को उच्चतम न्यायालय से भी कोई राहत नहीं मिली है, अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल जल्द ही जेल से बाहर आ पाएंगे। पार्टी को भारी वित्तीय संकट का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसका दैनिक कामकाज ठप हो गया है। दानदाता इसके उम्मीदवारों को धन देने में अनिच्छुक हैं क्योंकि विभिन्न जांच एजेंसियां आप की गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रही हैं। ऐसे में सबकी निगाहें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर टिकी हैं। वह एक पूर्ण मुख्यमंत्री हैं और वरीयता क्रम में 14वें नंबर पर सूचीबद्ध केजरीवाल की तुलना में 7वें नंबर पर हैं। दूसरे, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अच्छे संबंध हैं। एक सीमावर्ती राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते, केंद्र सतर्क है और उन्हें बिना वजह छेड़ना नहीं चाहेगा। मान भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना करते समय सावधान रहते हैं। उनके पास विशाल संसाधन हैं और वे अपने माध्यम से पार्टी उम्मीदवारों और जरूरतमंद नेताओं की मदद करते हैं। भाजपा नेतृत्व चाहता था कि पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए आप-कांग्रेस गठबंधन न करें। राजनीतिक विश्लेषक इस टूट के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि भगवंत सिंह मान ने शुरू से ही कांग्रेस के साथ गठबंधन के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया था और उनकी इच्छा पूरी हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही नए आवासीय परिसरों में शिफ्ट होंगे। यदि धनखड़ अप्रैल के पहले सप्ताह में नए घर में शिफ्ट होंगे, तो पीएम के 4 जून के बाद नए घर में जाने की संभावना है। नए उपराष्ट्रपति का आवास 15 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और इसमें बिल्ट-अप एरिया 20000 वर्ग फुट का है। इसमें एक मंजिला (ग्राउंड प्लस एक बेसमेंट के साथ) आवास, एक सचिवालय भवन, गेस्ट हाउस, खेलों की सुविधा, स्टाफ क्वार्टर और सहायक भवन होंगे। उपराष्ट्रपति आवास नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है, और इसके पास ही नया प्रधानमंत्री आवास होगा। पता चला है कि उपराष्ट्रपति अगले महीने नए आवासीय परिसर में शिफ्ट हो जाएंगे। नए आवासीय परिसर अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं और इनमें सभी सुरक्षा सुविधाएं हैं।

क्या वाकई आसान है यूपी में भाजपा की राह?

अनिल सिंह

लोकसभा की चार सौ सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी भाजपा को सबसे बड़ी उम्मीद उत्तर प्रदेश से है। इसलिए भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय कर रखा है। भाजपा के शीर्ष रणनीतिकार मान कर चल रहे हैं कि भाजपा उत्तर प्रदेश में 75 से अधिक सीटें जीतेगी, क्योंकि अपना दल, रालोद, सुभासपा, निषाद पार्टी जैसी जातीय आधारित पार्टियां उसके गठबंधन का हिस्सा हैं। इन जातियों का एकमुश्त वोट भाजपा प्रत्याशियों को मिलेगा। भाजपा को यूपी में फिलहाल सब फील गुड लग रहा है। परंतु, जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। भाजपा को उत्तर प्रदेश में जीत की राह जितनी आसान नजर आ रही है, वास्तव में यह उतनी सुगम है नहीं। भाजपा को मोदी लहर पर भरोसा होता तो जेपी नड्डा और अमित शाह पारिवारिक एवं जातीय पार्टियों से गठबंधन के लिए अपने घोड़े नहीं खोलते।

पार्टी नेतृत्व को अगर भरोसा होता कि नरेंद्र मोदी के नाम पर देश में लहर चल रही है, और पार्टी बिना किसी सहयोग के उत्तर प्रदेश में जीत हासिल हो जायेगी, तब सुभासपा एवं रालोद जैसी जातीय एवं पारिवारिक पार्टियों को गठबंधन में शामिल करने के लिये हाथ-पैर नहीं मारना पड़ता। %अपनों% का हक काटकर इन दलों को सरकार एवं विधान परिषद में हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ती। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा दावा कर रही है कि मतदाता उसे झूमकर वोट करेगा, लेकिन उसे भी इस थ्योरी पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। तभी भाजपा को मजबूरी में उन्हीं जातीय एवं पारिवारिक दलों को गठबंधन का हिस्सा बनाना पड़ा, जिन पर नरेंद्र मोदी अक्सर अपने भाषणों में हमला करते रहते हैं। विधानसभा चुनाव में जब सुभासपा और रालोद विपक्षी गठबंधन का हिस्सा थे, इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बहुमत हासिल किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इनके बिना लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। जाहिर है भाजपा को भरोसा नहीं है कि वह अकेले लड़कर उत्तर प्रदेश का किला फतह कर सकती है। सत्ता विरोधी लहर नहीं होने के बावजूद भाजपा को दो मोर्चों पर

विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी को एकमुश्त वोट देने वाला क्षत्रिय एवं कायस्थ मतदाता भाजपा से नाराज है। क्षत्रियों एवं कायस्थों का 90 फीसदी वोट भाजपा को मिलता रहा है, लेकिन अब इसमें बिखराव की आशंका है।

क्षत्रियों को लग रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उनके प्रतिनिधित्व को कम करने की साजिश कर रहा है। हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्यों में एक भी क्षत्रिय उम्मीदवार को टिकट नहीं देने तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की संख्या कम किये जाने को क्षत्रिय अपने साथ धोखा मान रहा है। उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय बहुल सीटों पर दूसरी जातियों के प्रत्याशी उतारे जाने से भी नाराजगी है। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर वैश्य समाज से आने वाले अतुल गर्ग को पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन कानपुर में ब्राह्मण सतीश पचौरी का टिकट काटकर उसी वर्ग के रमेश अवस्थी को, तो मेरठ से राजेन्द्र अग्रवाल का टिकट काटकर अग्रवाल समाज के ही अरुण गोविल को टिकट दिया गया। अन्य सीटों पर भी ऐसा ही बदलाव हुआ, लेकिन गाजियाबाद की क्षत्रिय सीट पर वैश्य को टिकट दे दिया गया। इसी का परिणाम है कि गाजियाबाद में क्षत्रिय बहुल इलाकों में अतुल गर्ग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गाजियाबाद में प्रत्याशी बदलाव का असर नोएडा, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर और मेरठ सीट पर भी पड़ने की संभावना है, क्योंकि इन लोकसभा सीटों की कई विधानसभा सीटों में क्षत्रिय मतदाताओं की निर्णायक संख्या है। पूर्वांचल में ओमप्रकाश राजभर के आने के बावजूद भाजपा को कई सीटों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जौनपुर के दबंग नेता धनंजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद हुई कार्रवाई है। हालांकि धनंजय को उनके खिलाफ दर्ज मामले में सजा मिली है और यह एक नियमित प्रक्रिया है, लेकिन सजा की टाइमिंग को लेकर नाराजगी है। धनंजय सिंह के समर्थकों को लग रहा है कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर चुनाव के समय ही धनंजय को सजा दिलवाई है ताकि वह मैदान में नहीं उतर सकें।

हालांकि भाजपा को क्षत्रियों की नाराजगी से सीटों की संख्या पर कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। वह मानकर चल रही है कि थोड़ा बहुत क्षत्रिय मतदाता इधर उधर होगा, तो उसकी भरपायी राजभर एवं जाट वोटर कर देगा। राम मंदिर निर्माण का असर भी क्षत्रियों की नाराजगी दूर करने में मदद करेगा लेकिन संभव है कि यह भाजपा की बड़ी भूल साबित हो। क्षत्रिय वोटर मान कर चल रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को आगे करके क्षेत्रीय क्षत्रपों को खत्म करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस नाराजगी का असर केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। क्षत्रियों के अलावा कायस्थ वोटरों में भी भाजपा के खिलाफ नाराजगी है। कायस्थ लंबे समय से आंख मूंदकर भाजपा पर भरोसा करता आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों राज्यसभा एवं विधान परिषद के लिए हुए चुनाव में भाजपा ने एक भी कायस्थ प्रत्याशी नहीं उतारा। कायस्थ को लग रहा है कि भाजपा ने उसे अपना बंधुवा वोटर समझ लिया है, इसलिए पार्टी में अन्य जातियों को उनकी हिस्सेदारी मिल रही है, लेकिन कायस्थ हाशिये पर है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, फूलपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, गोरखपुर, बनारस, लखनऊ, बरेली, देवरिया, बलिया, जौनपुर, रायबरेली, कानपुर लोकसभा सीट पर कायस्थों की अच्छी खासी संख्या है। प्रयागराज, गोरखपुर, बरेली जैसी सीटों पर तो कायस्थ वोटर परिणाम बदल सकता है। कायस्थ वोटर प्रकियावादी नहीं होता है, इसलिए भाजपा इस वर्ग को गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन सपा की लंबे समय से कायस्थ वोटरों पर नजर है।

महाराष्ट्र में आगाज यदि ये है तो अंजाम क्या होगा!

अमिताभ श्रीवास्तव

लोकसभा चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 24, शिवसेना ठाकरे गुट ने 17, शिवसेना के शिंदे गुट ने आठ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) अजित पवार गुट ने दो, कांग्रेस ने सात उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राकांपा शरद पवार की ओर से बारामती से सुप्रिया सुले और रावेर से रोहिणी खड़से के नाम अघोषित तौर पर उम्मीदवारों की सूची में माने जा रहे हैं। यूं देखा जाए तो इस चुनाव में राज्य के उम्मीदवारों की सूची जारी करने में भाजपा सबसे आगे रही और उसने अपने 20 उम्मीदवार घोषित किए।

उसके बाद भाजपा ने कुछ और नामों की घोषणा की। इस बीच, वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी नौ नामों की घोषणा कर मराठा आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मनोज जरांगे से तालमेल का ऐलान कर दिया। माना यह जा रहा था कि लंबी माथापच्ची के बाद घोषित किए गए आधे नामों का स्वागत होगा, लेकिन किसी भी दल में आनंद की स्थिति नहीं है। विदर्भ में चंद्रपुर सीट से चुनाव लड़ने के अनिच्छुक राज्य सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को भाजपा का टिकट मिला तो मन मारकर उन्हें पार्टी के निर्देश का पालन करना पड़ा। वहीं जब अमरावती में निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भाजपा ने टिकट दिया तो प्रहार पार्टी के नेता बच्चू कडू नाराज हो उठे। मराठवाड़ा में औरंगाबाद लोकसभा सीट पर शिवसेना ठाकरे गुट से चंद्रकांत खैरे को टिकट मिलने से पार्टी के विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे नाखुश समझे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी चुनाव लड़ना था। जालना में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री रावसाहब दानवे का नाम एकतरफा समझ कर घोषित कर दिया।

वहां शिवसेना शिंदे गुट के नेता अर्जुन खोतकर खुश नहीं हैं। पिछले चुनावों में भी खोतकर को मनाने में दानवे को काफी मेहनत करनी पड़ी थी। शिर्डी लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को नजरअंदाज किया गया, जबकि अहमदनगर में सुजय विखे को लेकर पार्टी में सकारात्मक माहौल नहीं है।

नासिक में हेमंत गोडसे के नाम पर सहमति नहीं है और वहीं राज्य सरकार के मंत्री छगन भुजबल भी परिस्थितियों पर नजर रखे हैं। मुंबई में ठाणे सीट की दिक्कत, कांग्रेस नेता संजय निरुपम की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। उधर सांगली, सातारा से लेकर कोल्हापुर में उदयनराजे भोसले से लेकर कई दुःखी इच्छुक उम्मीदवारों का भी संकट बना हुआ है। ये कुछ ऐसे मामले हैं जो सतह पर दिख रहे हैं, किंतु आंतरिक स्थितियां अधिक नाजुक हैं। दरअसल, राज्य के प्रमुख दलों में बिखराव के बाद राजनीतिक स्थितियां चुनौती और महत्वाकांक्षा के बीच उलझ रही हैं। टूट कर बने नए दलों का आधार ही महत्वाकांक्षा है, जबकि उनके मूल दल टूट के बाद दोबारा खड़ा होना अपनी चुनौती मान चुके हैं।

नए दल जोड़-तोड़ के फार्मूले पर एक-दूसरे को भरोसा दिला कर तैयार हुए हैं। उनमें शामिल हर नेता की पार्टी से अपनी अपेक्षा है। यदि किसी नेता की उम्मीदों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा या मांगों को लेकर गंभीरता नहीं है, तो उसका बागी तेवर स्वाभाविक स्थिति है। इसी प्रकार यदि मूल दल में बचे नेता की निष्ठा की कीमत नहीं मिल रही, तो वहां भी परेशानी सहज ही है। राज्य में अभी तक शिवसेना शिंदे गुट, भाजपा और राकांपा अजित पवार गुट के महागठबंधन ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर अपने तालमेल का ऐलान नहीं किया है। हालांकि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने 28 मार्च को संवाददाता सम्मेलन में सीटों के तालमेल की घोषणा करना जाहिर किया था। इसी प्रकार शिवसेना उद्धव गुट, कांग्रेस और राकांपा शरद पवार गुट की महाआघाड़ी ने तालमेल की बात तो दूर, अपने-अपने स्तर पर उम्मीदवारों के नाम घोषित करने आरंभ कर दिए हैं। साफ है कि किसी भी गठबंधन में सीटों के बंटवारे के फार्मूले तय नहीं होने से अपनी डफली अपना राग ही चल रहा है।

लोकसभा चुनाव के मुहाने पर असमंजस, मनमुटाव, विरोधाभास और खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलहाल सवाल तो यह भी है कि राज्य की 48 लोकसभा सीटों के बंटवारे के लिए यदि कोई तालमेल नहीं बन पा रहा है तो कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की 288 सीटों के लिए किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी? वह भी तब, जब हर दल में एक मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी होगा। यदि राज्य के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर नजर दौड़ाई जाए तो भाजपा और कांग्रेस में अभी-भी मूल नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या दिखाई देती है, जिसमें कैडर बेस काम करने और अनुशासन में रहने का महत्व अधिक दिखता है। वहीं टूटे और बिखर कर बने दलों में हर नेता की अपनी आकांक्षा और अपेक्षा है। चूंकि उन्होंने अपने मूल दल से बगावत की है, इसलिए उनके पास सिद्धांत और संयम के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी में बागी नेताओं के नेतृत्व की समस्या छिपी हुई है, जिसका हल आसान नहीं है। जिससे दूरगामी परिणामों पर भी आशंकाएं मंडरा रही हैं। ऐसे में यदि नए राजनीतिक समीकरणों का आगाज इस तरह है तो अंजाम क्या होगा, जो निश्चित ही लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे। जिनके लिए आगामी चार जून तक इंतजार करना होगा।

47 वर्षों बाद फिर रायबरेली-अमेठी से गांधी परिवार को वनवास !

अजय कुमार

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सपा से समझौते के तहत कांग्रेस को यह सीटें मिली हैं। सपा और कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, इसलिये जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उस सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नहीं होगा। कांग्रेस को 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी से एक सीट जीतने में सफलता मिली थी और पूरे प्रदेश में उसका वोट मात्र दो फीसदी के करीब था। 2019 से आज तक कांग्रेस की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है, बल्कि गिरावट ही देखने को मिली है। कांग्रेस की हालत इतनी दयनीय है कि गांधी परिवार तक यूपी से चुनाव लड़ने की ताकत नहीं जुटा पा रहा है। 2019 में राहुल गांधी अमेठी हार गये थे तो 2024 में सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली को टाटा- बाय-बाय कह दिया है। वह राज्यसभा की सदस्य बन गई हैं। अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की आज जैसी दयनीय स्थिति 47 वर्ष पूर्व 1977 में देखने को मिली थी, जब इमरजेंसी के बाद हुए लोकसभा चुनाव में रायबेरली से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को समाजवादी राजनारायण सिंह से और अमेठी से संजय गांधी को हार का मुंह देखना पड़ा था। 1977 और 2024 के आम चुनाव में बस अंतर इतना है कि 1977 में गांधी परिवार की तानाशाही के चलते वोटरों ने उसको ठुकरा दिया था,लेकिन 47 वर्षों के बाद 2024 में गांधी परिवार को विश्वसनीयता के संकट के कारण रायबरेली-अमेठी से दूर भागना पड़ रहा है। गौरतलब हो, रायबरेली और अमेठी का नाम आते ही गांधी परिवार की चर्चा सबसे पहले शुरू होती है। असल में यहां की राजनीतिक तस्वीर गांधी परिवार के इर्दगिर्द घूमती रही है तो यहां की जनता ने गांधी को गांधी से लड़ते हुए भी देखा है। यहां पर दो बार गांधी परिवार के बीच ही मुकाबला हो चुका है। हैरानी की बात तो यह है कि दोनों बार विरासत एक बड़ा मुद्दा था। पहले चुनाव में वारिस कौन तो दूसरे चुनाव में असली गांधी कौन की गूंज। यह बात अलग है कि दोनों चुनावों में शिकस्त खाने वाले गांधी ने दोबारा से अमेठी की तरफ घूमकर भी नहीं देखा। वर्ष 1980 में संजय गांधी ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की। उसी साल विमान हादसे में उनकी मौत के बाद 1981 में हुए उपचुनाव में राजीव गांधी मैदान में उतरे। यहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। इसके बाद सियासत ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। वर्ष 1984 का चुनाव उस वक्त दिलचस्प हो गया जब कांग्रेस के राजीव गांधी के सामने उनके स्वर्गीय छोटे भाई संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने निर्दल प्रत्याशी के तौर पर मोर्चा खोल दिया। 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ मैदान में उतरने वाली मेनका गांधी ने 1982 से ही अमेठी में सक्रियता बढ़ा दी थी। ऐसे में जब वह 1984 में चुनाव में उतरीं तो अमेठी की जनता उलझन में पड़ गई। एक ओर इंदिरा की हत्या के बाद जनता की सहानुभूति राजीव गांधी के साथ थी तो वहीं दूसरी ओर अमेठी के सांसद रहे संजय गांधी की विधवा मेनका गांधी के प्रति आत्मीय लगाव, लेकिन बाजी राजीव ने ही मारी। वर्ष 1984 में राजीव गांधी को प्रचार के लिए पहली बार सोनिया गांधी को मैदान में उतारना पड़ा। हालांकि उस वक्त सोनिया ने कोई सभा तो नहीं की, लेकिन वह घर-घर जाकर महिलाओं से मिल रही थीं। पूरे चुनाव तक उन्होंने ही प्रचार की बागडोर संभाली। दूसरा मुकाबला वर्ष 1989 में हुआ, जब कांग्रेस के राजीव गांधी के सामने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी ने ताल ठोंक दी। उस वक्त जनता दल व भाजपा ने संयुक्त रूप से राजमोहन गांधी पर भरोसा जताया था। इस चुनाव में असली बनाम नकली गांधी का मुद्दा खूब उछला। कई बड़े दिग्गज नेताओं ने सभा की। आरोप प्रत्यारोप के खूब शब्दवाण चले, लेकिन अमेठी की जनता ने एक बार फिर राजीव गांधी का साथ दिया, लेकिन इससे उलट आज अमेठी-रायबेरली में गांधी परिवार की स्थिति काफी दयनीय हो गई है।

आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं अष्टचिरंजीवी

किसी को श्राप तो किसी को वरदान से प्राप्त हुआ अमरत्व

अष्ट चिरंजीवी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। चिरंजीवी उन्हें कहा जाता है, जो अमर होता है यानी की उनका कभी अंत नहीं होता है। वहीं हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक पृथ्वी पर एक-दो नहीं बल्कि 8 चिरंजीवी मौजूद हैं। जिनका कभी अंत नहीं होगा और इनमें से कुछ को अमरता का वरदान प्राप्त है। तो वहीं कुछ श्राप के कारण अमर हो गए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इन 8 चिरंजीवी के बारे में बताने जा रहे हैं।

हनुमान जी

माता सीता द्वारा हनुमान जी को अमरता का वरदान मिला है। जब प्रभु श्रीराम का संदेश लेकर हनुमान मां सीता के पास अशोक वाटिका पहुंचे। तो मां सीता हनुमानजी की भक्ति व श्रीराम के प्रति समर्पण देख अति प्रसन्न हुईं। जिसके बाद सीताजी ने हनुमान को अमरता का वरदान दिया। मान्यता के अनुसार, आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर वास करते हैं और प्रभु श्रीराम की भक्ति में लीन हैं।

अश्वत्थामा

जहां कुछ चिरंजीवी को अमरता का वरदान मिला, तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए। इस लिस्ट में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का नाम शामिल है। महाभारत युद्ध के दौरान पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अनीति का रास्ता अपनाया। अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का निद्रा में वध कर दिया। तब भगवान श्रीकृष्ण ने अश्वत्थामा को क्रोधित होते हुए श्राप दिया कि पृथ्वी के अंत तक घावों से लथपथ शरीर लेकर अश्वत्थामा भटकता रहेगा और उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। श्रीकृष्ण के श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है।

राजा बलि

प्रह्लाद भगवान श्रीहरि विष्णु के परम भक्त थे और राजा बलि प्रह्लाद का वंशज है। जब श्रीहरि वामन रूप धारण कर राजा बलि की परीक्षा लेने आए, तो बलि ने भगवान वामन को अपना सबकुछ दान कर दिया था। राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान श्रीहरि ने उनको अमरता का वरदान दिया। माना जाता है कि राजा बलि आज भी पाताल लोक में वास कर रहे हैं।

विभीषण

विभीषण लंकापति रावण का सबसे छोटा भाई था। विभीषण को भी अमरता का वरदान प्राप्त था और यह वरदान स्वयं श्रीराम ने दिया था। बताया जाता है कि रावण के वध के बाद श्रीराम ने विभीषण को सोने की लंका सौंप दी थी और साथ ही अमरत्व का वरदान दिया था। वर्तमान में भी विभीषण पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं।

परशुराम

परशुराम भगवान शिव के परभक्त थे। साथ ही वह भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। परशुराम हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने परशुराम को अमरता का वरदान दिया था। वहीं महाभारत और रामायण दोनों में ही परशुराम का उल्लेख मिलता है।

कृपाचार्य

बता दें कि कृपाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु हैं। महाभारत के युद्ध में कौरवों की तरफ से ऋषि कृपाचार्य ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। कृपाचार्य का नाम परम तपस्वी ऋषियों में शामिल हैं। कृपाचार्य के तप की वजह से उन्हें अमरता का वरदान मिला था।

वेदव्यास

महर्षि वेदव्यास ने चारों वेद ऋवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रचनाकार हैं। महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई। इनको भी अमरता का वरदान प्राप्त है।

ऋषि मार्कंडेय

ऋषि मार्कंडेय 8 चिरंजीवियों में शामिल हैं। वह भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि मार्कंडेय ने शिव के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्यंज्य मंत्र की रचना भी की थी। हांलाकि वह अल्पायु लेकर जन्मे थे। लेकिन स्वयं भगवान शिव यमराज से उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए। भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया था।

● अनन्या मिश्रा

सूर्य को जल चढ़ाने से भाग्य का मिलता है साथ

जानिए इसका धार्मिक और वैज्ञानिक कारण

हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का स्थान प्राप्त है। सूर्य के बिना धरती पर अंधकार छा जाता है। वहीं सूर्यदेव को जल अर्पित करने के अनगिनत फायदे होते हैं। सूर्य को जल अर्पित करने से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक लाभ प्राप्त होता है और आर्थिक उन्नति मिलती है। सूर्य अच्छी सेहत और जीवन शक्ति का भंडार है। बताया जाता है कि आप सूर्य के प्रभाव में जितना अधिक रहेंगे आप उतना ही अधिक सेहतमंद रहेंगे। हांलाकि आजकल लोग सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए चारों तरफ से खिड़कियां-दरवाजे बंद रखते हैं। इसी वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी होती है और अन्य कई रोग हमें घेर लेते हैं। सूर्य के प्रकाश का और सूर्य को जल अर्पित करने का अपना धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है।

वैज्ञानिक महत्व और लाभ- विज्ञान के मुताबिक सूर्य को जल अर्पित करने के दौरान जब हम पानी की धाराओं में से सूर्य की तरफ देखते हैं। तो उससे निकलने वाली 7 तरह की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं। इन किरणों से आंखों को लाभ मिलता है और आंख की रोशनी अच्छी होती है। साथ ही आंखों का रंग भी नेचुरल बना रहता है। बता दें कि जो लोग रोजाना सूर्य को जल चढ़ाते हैं, उनको आंख संबंधी रोग नहीं होते हैं। वहीं सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है।

धार्मिक महत्त्व और लाभ - अथर्ववेद के एक मंत्र के अनुसार, सूर्य औषधि बनाने में सहायक है। सूर्य विश्व में प्राण स्वरूप विद्यमान है और यह अपनी किरणों से जीवों के स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। रविवार का दिन सूर्य को समर्पित होता है और भगवान सूर्य सप्तमी तिथि के देवता है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ऊं घृणि सूर्याय नमः या ऊँ आदित्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बता दें कि सूर्य को भाग्य का कारक माना जाता है। जिन जातकों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है। उनके सरकारी कार्यों में रुकावट आती है और व्यापार नहीं सही चलता है। कार्यस्थल पर हमेशा उच्च पदाधिकारियों से अनबन होती रहती है।

सूर्य को ऐसे करें मजबूत- आपको बता दें कि रोजाना सूर्य को जल अर्पित कर आप कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। इससे सूर्य देव प्रसन्न होकर अपने भक्तों के संकटों को हर लेते हैं। साथ ही धन-धान्य, पुत्र, मित्र, आरोग्य, यश, तेज, कांति, विद्या, वैभव और सौभाग्य प्रदान करते हैं। सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए रोजाना जल अर्पित करने के साथ ही हर रविवार या फिर किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के रविवार को नदी या बहते जल में गुड़ और चावल प्रवाहित करने चाहिए।

जैन धर्म में मृत्यु पर इस तरह विजय प्राप्त करते हैं संत

काफी कठिन है समाधि की अनोखी परंपरा

हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी महासमाधि ली जाती है। लेकिन जैन धर्म की समाधि को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है। तो आज हम आपको सल्लेखना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं।

हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म में भी महासमाधि ली जाती है। लेकिन जैन धर्म की समाधि को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है। जैसे जैन धर्म में समाधि के क्या मायने होते हैं। समाधि कैसे ली जाती है और सल्लेखना क्या होता है। साथ ही इसको खुदकुशी क्यों कहा जाता है। ऐसे में अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल रहते हैं। तो यह आर्टिकल आपके लिए है। क्योंकि आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं।

क्या होता है सल्लेखना- आपको बता दें कि जैन संतों द्वारा ली जाने वाली समाधि को सल्लेखना कहा जाता है। जैन धर्म के मुताबिक सल्लेखना एक तरह की आत्महत्या है। सल्लेखना के जरिए जैन संत नश्वर जीवन की मुक्ति के बिना ही विशेष कर्मकांड के प्राप्त करते हैं। लेकिन जैन धर्म में सल्लेखना से जुड़े कुछ नियम भी मौजूद होते हैं। जैन धर्म में यदि किसी संत को सल्लेखना या समाधि लेते है। तो उनको संपत्ति संचय, झूठ बोलना, अहिंसा और चोरी जैसे कृत्यों को त्याग करना पड़ता है।

क्योंकि असल में इस धर्म में सल्लेखना की परंपरा बेहद खास मानी जाती है। वहीं इस सल्लेखना परंपरा का पालन मृत्यु आने पर किया करते हैं। जब जैन धर्म में किसी को लगता है कि उसकी मृत्यु आने वाली है। वहीं कुछ दिनों में उसका शरीर प्राण को छोड़ सकता है। तब व्यक्ति खुद से भोजन और जल का त्याग करता है। बता दें कि दिगंबर जैन शास्त्र के मुताबिक इसको ही महासमाधि या सल्लेखना कहा जाता है।बताया जाता है कि सल्लेखना यानी महासमाधि का पालन करना बेहद कठिन होता है। सल्लेखना के दौरान शरीर को अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। इस परंपरा का अपना इतिहास भी है। इसके अनुसार, 'जैन' शब्द की उत्पत्ति जिस से हुई है, जिसका अर्थ 'विजेता' होता है। जैन धर्म में मृत्यु को विजय माना गया है। जैन धर्म के संत जब सल्लेखना लेते हैं, तब मृत्यु का समय विजय प्राप्त करने के समान होता है। इसी वजह से सल्लेखना के दौरान इन नियमों का पालन करना इस धर्म में सबसे ज्यादा अहम माना गया है।

माता सीता को मुंह दिखाई में मिला था अयोध्या का यह महल

अयोध्या स्थित राम मंदिर कई चीजों के लिए फेमस है। भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में कई ऐसे धार्मिक स्थल, भवन, इमारत, मंदिर और महल मौजूद हैं। जो किसी न किसी रूप में रामायण काल से जुड़ी है।

आपको बता दें कि प्रभु राम की नगरी आयोध्या में एक ऐसा महल भी है, जिसके बारे में बताया जाता है यह माता सीता को मुंह दिखाई में मिला था। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको इस महल से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में बताने जा रहे हैं।

कनक महल

बताया जाता है कि माता सीता को मुंह दिखाई में जो महल मिला था, उसका नाम कनक भवन था। जब प्रभु श्रीराम जनक नंदनी से विवाह के बाद अयोध्या पहुंचे थे, तो महारानी कैकेयी ने मां सीता को मुंह दिखाई में उपहार स्वरूप कनक महल दिया था। मान्यता के मुताबिक देवी सीता और प्रभु श्रीराम का यह कनक महल निजी महल हुआ करते थे। हर दिन हजारों की संख्या में इस महल को देखने के लिए लोग अयोध्या पहुंचते हैं। वर्तमान समय में कनक महल अयोध्या के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है।

देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था कनक महल- कनक महल के निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एक दिन महारानी कैकेयी ने अपने सपने में एक दिव्य महल देखा। अगले दिन महारानी ने राजा दशरथ से अपने स्वप्न के बारे में बताया और ठीक वैसा ही महल बनवाने की इच्छा जताई। महारानी कैकेयी की महल बनवाने की इच्छा के बाद महाराजा दशरथ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर एक भव्य और सुंदर महल का निर्माण करवाया था। वहीं प्रभु राम की शादी के बाद माता सीता के अयोध्या आने पर महारानी कैकेयी ने उन्हें मुंह दिखाई में कनक महल दिया था।

कनक महल की पौराणिक कथा - कनक महल की पौराणिक कथा बहुत दिलचस्प है। लोक मान्यता के अनुसार, द्वापर युग में प्रभु श्रीकृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी समेत अयोध्या पहुंचे, तब कनक भवन खंडहर बन चुका था। लेकिन फिर भी भगवान श्रीकृष्ण को टीले पर आनंद आता था। ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण ने दिव्य दृष्टि से देखा कि यह कनक महल है। तब श्रीकृष्ण ने अपने योगबल से श्री सीताराम की मूर्तियों को प्रकट कर स्थापित किया था।

महल का जीर्णोद्धार- कनक महल में स्थापित शिलालेखों से जानकारी मिलती है, इस महल का कई बार जीर्णोद्धार किया जा चुका है। बताया जाता है कि सबसे पहले श्रीराम के पुत्र कुश ने कनक महल का जीर्णोद्धार कराया था। साथ ही उन्होंने महल में भगवान श्रीराम और मां सीता की मूर्तियां स्थापित करवाई थीं। वहीं कुश के बाद श्रीकृष्ण ने इस महल का पुनर्निर्माण करवाया था। इसके अलावा चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त द्वारा भी इस महल का पुनर्निर्माण किया था। बताया जाता है कि वर्तमान समय में महल का जो स्वरूप मौजूद है, उसको राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी वृषभानु द्वारा बनवाया गया है।

बेहद खास हैं कनक भवन की मूर्तियां- कनक महल को मंदिर के तौर पर भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्रीराम, मां सीता, श्रीलक्ष्मण और भरत-शत्रुघ्न विराजमान हैं। अयोध्या का यह इकलौता ऐसा महल है, जहां पर प्रभु श्रीराम माता सीता के साथ अपने भाइयों के साथ विराजमान हैं।

इस समय घूमने जाएं- वैसे तो आप कभी भी कनक महल घूमने के लिए जा सकते हैं। गर्मियों में सुबह 08 बजे से लेकर रात के 09 बजे तक घूम सकते हैं। वहीं सर्दियों में सुबह 09 बजे से रात 08 बजे के बीच घूमने के लिए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

केजरीवाल को जेल, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा

नईदिल्ली। 10 दिन तक सवाल करने के बाद

आज जब शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल का नया पता अब तिहाड़ जेल है। जी हां, ईडी ने कोर्ट के समक्ष केजरीवाल को पेश किया और कहा कि रिमांड के दौरान केजरीवाल सही से जवाब नहीं दे रहे है और सवालों को उलझाने की कोशिश कर रहे है। इन तमाम आरोपों के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से न्यायिक हिरासत की मांग की गई थी जिसे पीएमएलए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और 15 अप्रैल तक केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा। कोर्ट के सामने ईडी ने कहा कि केजरीवाल जवाब देने में टाल मटोल कर रहे है और कोई भी जवाब स्पष्टता के साथ नहीं दे रहे है। साथ ही उन्होंने केजरीवाल के न्यायिक हिरासत की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी हो कि वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में रहेंगे।

चुनाव तक कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा आईटी

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को कुछ राहत मिली है।

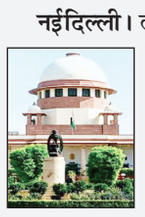

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में 3,500 करोड़ रुपये के टैक्स मामले पर सोमवार को कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह लोकसभा चुनावों को देखते हुए 3,500 करोड़ रुपये के टैक्स मांग नोटिस के संबंध में कांग्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया। शीर्ष कोर्ट ने टैक्स मांग के खिलाफ कांग्रेस की याचिका की सुनवाई जुलाई 2024 तक के लिए स्थगित कर दी। कांग्रेस ने 135 करोड़ रुपये के टैक्स की मांग के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसपर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि अभी कांग्रेस के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पूर्णिया सीट पर अड़े पप्पू यादव, 4 को करेंगे नामांकन

पटना। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस

पार्टी में शामिल हुए राजद के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वह बिहार की पूर्णिया सीट से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और 4 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पहले 2 अप्रैल को वह नामांकन करने वाले थे। उन्होंने लालू यादव के लिए एक संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि मैं बस लालू यादव को बताना चाहता हूं कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं। जब भी लालू का परिवार संकट में रहा है, मैं वहां गया हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी ताकत का भी एहसास कराने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मधेपुरा, सुपौल या गठबंधन की राजनीति मेरे लिए व्यक्तिगत नहीं है। पूर्णिया की जनता किसी की गुलाम नहीं है। वे पटना और दिल्ली की राजनीति से दूर हैं और वे अपने बेटे से प्यार करते हैं, दिल्ली और पटना में रहने वालों से नहीं। अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने वाले पप्पू यादव अब अपने फैसले पर पछताते दिख रहे हैं।

कमलनाथ के गृह नगर के महापौर भाजपा में शामिल

भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को

उस समय एक और झटका लगा जब सोमवार सुबह उसके नेता और छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गये। अहाके राज्य की राजधानी भोपाल में राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख वी.डी. शर्मा की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा से कांग्रेस विधायक कमलेश शाह पिछले सप्ताह भाजपा में शामिल हो गए थे। शाह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी सहयोगी थे। छिंदवाड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है जहां 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। मध्य प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एकमात्र विजेता नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस सीट का उनके पिता कमलनाथ ने संसद में नौ बार प्रतिनिधित्व किया है।

आप के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी कांग्रेस में शामिल

चंडीगढ़। पंजाब के पटियाला से आम

आदमी पार्टी (आप) के पूर्व सांसद धर्मवीर गांधी लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को यहां कांग्रेस में शामिल हो गये। धर्मवीर के पटियाला सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। गांधी ने 2014 में आप के उम्मीदवार के रूप में परनीत कौर को हराकर लोकसभा चुनाव जीता था। बाद में, पेशे से चिकित्सक गांधी ने 2016 में आप छोड़ कर अपना खुद का दल 'नवां पंजाब पार्टी' बनाया। उन्होंने सोमवार को इस दल का कांग्रेस में विलय कर दिया। पार्टी नेता पवन खेड़ा और पंजाब के प्रभारी देवेन्द्र यादव, कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने गांधी का पार्टी में स्वागत किया। बाजवा ने कहा कि उनके शामिल होने से कांग्रेस मजबूत होगी। वड़िंग ने कहा कि ऐसे पेशेवरों का पार्टी में शामिल होना एक अच्छा संकेत है।

कच्चातिवु द्वीप : मोदी ने विपक्ष को दिखाया आइना!

नरेंद्र मोदी ने डीएमके और कांग्रेस को घेरा, कहा- उन्हें केवल अपने बेटे-बेटियों की फिक्र

चेन्नई। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि कच्चातिवू द्वीप मुद्दे पर नए विवरण ने द्रमुक के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। उनकी यह टिप्पणी 1970 के दशक में इस रणनीतिक द्वीप को श्रीलंका को सौंपने के फैसले पर कांग्रेस पर हमला करने के एक दिन बाद आई है। एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधान मंत्री ने कहा, बयानबाजी के अलावा, डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया है। कच्चाथीवू पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस और द्रमुक पारिवारिक इकाइयां हैं। उन्हें केवल इसकी परवाह है कि उनके अपने बेटे और बेटियां आगे बढ़ें। उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कच्चातिवू पर उनकी उदासीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और मछुआरे महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है।

कच्चाथीवू द्वीप वह स्थान है जहां तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे द्वीप पर पहुंचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करते हैं, उन्हें श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है। रविवार को, प्रधान मंत्री मोदी ने न केवल श्रीलंका को द्वीप सौंपने के लिए कांग्रेस पर हमला किया, बल्कि पार्टी पर देश की अखंडता और हितों को कमजोर करने का भी आरोप लगाया।

उनकी टिप्पणी सूचना के अधिकार (आरटीआई) रिपोर्ट के जवाब में आई है, जिसमें पता चला है कि कैसे तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 1974 में कच्चातिवु को श्रीलंका को सौंप दिया था। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया आंखें खोलने वाली और चौंका देने वाली! नए तथ्यों से पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चाथीवू को दे दिया। इससे हर भारतीय नाराज है और लोगों के मन में फिर से पुष्टि हुई है - हम कभी भी कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर सकते! भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा है 75 साल और गिनती जारी है।

इसके अलावा सोमवार को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कच्चाथीवू द्वीप विवाद पर द्रमुक और कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने इस मामले

को ऐसे देखा जैसे कि उनकी इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है।

दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जयशंकर ने कहा, पिछले 20 वर्षों में, 6,184 भारतीय मछुआरों को श्रीलंका द्वारा हिरासत में लिया गया है और 1,175 भारतीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है या पकड़ा गया है। यह इस मुद्दे की पृष्ठभूमि है कि हम हैं।

जयशंकर ने कहा पिछले पांच वर्षों में, कच्चातिवू मुद्दा और मछुआरों का मुद्दा संसद में विभिन्न दलों द्वारा बार-बार उठाया गया है। यह संसद के प्रश्नों, बहसों और सलाहकार समिति में सामने आया है। तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुझे लिखा है कई बार। और मेरा रिकॉर्ड बताता है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को मैंने इस मुद्दे पर 21 बार जवाब दिया है। यह कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अचानक सामने आ गया हो। यह एक जीवंत मुद्दा है।

उन्होंने कहा कि हालांकि यह मामला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्राचार का विषय रहा है...तमिलनाडु में हर राजनीतिक दल ने इस पर अपना रुख अपनाया है। जयशंकर ने कहा, दो पार्टियों, कांग्रेस और द्रमुक, ने इस मामले को ऐसे उठाया है जैसे कि उनकी इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि स्थिति को आज की केंद्र सरकार को हल करना है, इसका कोई इतिहास नहीं है। विदेश मंत्री ने आगे दावा किया कि हम जानते हैं कि यह किसने किया, हम नहीं जानते कि इसे किसने छुपाया। हमारा मानना है कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई।

उन्होंने कहा यह मुद्दा बहुत लंबे समय से जनता की नजरों से छिपा हुआ है। मछुआरों को आज भी हिरासत में लिया जा रहा है, नौकाओं को अभी भी पकड़ा जा रहा है, और यह मुद्दा अभी भी संसद में उठाया जा रहा है। इसे दो दलों द्वारा संसद में उठाया जा रहा है जिन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा जब भी कोई गिरफ्तारी हुई, आपको क्या लगता है कि उन्हें कैसे रिहा किया गया? चेन्नई से बयान देना बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोग काम करते हैं वे हम हैं। रविवार को प्रधानमंत्री की टिप्पणी की कांग्रेस और द्रमुक दोनों ने आलोचना की।

जबकि कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने इस मुद्दे को हल करने और द्वीप को वापस लेने के लिए कोई कदम उठाया है, द्रमुक ने कहा कि भाजपा विपक्ष के साथ आरोप-प्रत्यारोप का खेल खेलने में व्यस्त है और आरोप लगाया कि वह डर रही है।

चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा- आज जो इसके खिलाफ नाच रहे हैं वे पछताएंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बॉन्ड योजना के खारिज होने को अपनी सरकार के लिए झटका मानने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को दिए एक साक्षात्कार में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अपनी बात रखी। रिपोर्टर के यह पूछने पर कि क्या इस योजना के कोर्ट से खारिज होने को सरकार के लिए झटका माना जाए, पीएम ने कहा-2014 से पहले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को मिले पैसे का कोई हिसाब नहीं मिलता था। मुझे बताइये ऐसा क्या हुआ है जिससे यह माना जाए कि यह मेरी सरकार के लिए झटका है। मैं पक्का मानता हूं कि जो लोग इसे लेकर आज नाच रहे हैं वो पछताने वाले हैं।

पीएम ने कहा, मैं पूछना चाहता उन सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए, उनमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा, तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया, कहां गया? मोदी ने चुनावी बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने लिया, किसे दिया। इसके कारण पैसे का ट्रेल पता चल रहा है। कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती, कमियां हो सकती हैं लेकिन उन्हें सुधारा जा सकता है।

मोदी के बयान पर स्टालिन का तीखा प्रहार

केंद्र से किए तीन सवाल, भाजपा पर लगाए आरोप

चेन्नई। कच्चातिवु द्वीप मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान और केंद्रीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पलटवार किया है। उन्होंने मछुआरों के प्रति अचानक भाजपा का प्यार जागने पर सवाल उठाया है। पीएम मोदी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले को लेकर आलोचना करने के बाद सीएम स्टालिन ने इसे ध्यान भटकाने वाली रणनीति बताया है।

मीडिया से बात करते हुए स्टालिन ने कहा, 10 वर्षों से कुंभकर्ण की नींद से उठने के बाद जो मछुआरों के प्रति अपना प्यार दिखा रहे हैं, तमिलनाडु की जनता उनसे तीन सवाल पूछना चाहती हैं। केंद्र सरकार तमिलनाडु द्वारा कर के रूप में दिए गए एक रुपये में से 29 पैसे क्यों लौटाती है? राज्य को दो प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा, इस दौरान केंद्र ने बाढ़ राहत के तौर पर तमिलनाडु को एक भी पैसा क्यों नहीं दिया? वह एक ऐसी परियोजना के बारे में बता दें जिसे पिछले दस वर्षों में उनके द्वारा राज्य में लागू किया गया है?

उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ध्यान भटकाने की रणनीति न करके वह (पीएम मोदी) पहले इन तीन सवालों का जवाब दें। इसी के साथ स्टालिन ने हैशटैग के साथ कहा बथिल सोलुंगा मोदी, जिसका मतलब है पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं।

कच्चातिवु द्वीप मामले को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने डीएमके पर इस मामले को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। जयशंकर के इस आरोप पर डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने पलटवार किया है। उन्होंने मीडिया से कहा, आप (भाजपा) यहां पिछले 10 वर्षों से सत्ता में है। इस दौरान भाजपा सरकार ने कच्चातिवु द्वीप को वापस पाने की कोशिश तक नहीं की। भाजपा अब ऐसा क्यों कर रही है? उन्हें मालूम है कि देशभर में वे 150 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। वह इस मुद्दे को इसलिए उठाना चाहते हैं, ताकि चुनावी बॉन्ड से सबका ध्यान भटक जाए।

पीएम मोदी पर भड़के कांग्रेस नेता

कच्चातिवु द्वीप को लेकर पीएम मोदी के पोस्ट और विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस नेता मनिकम टैगोर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु के लोग भाजपा को खारिज कर रहे हैं और पार्टी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

मीडिया से बात करते हुए अन्नादुरई ने कहा, भाजपा, आरएसएस और पीएम मोदी के साथ एक ही परेशानी है। तमिलनाडु के लोग उन्हें खारिज कर रहे हैं और वह ध्यान भटकाने की रणनीति चाहते हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था, जिसे इंदिरा गांधी-सिरीमावो भंडारनायके समझौता के नाम से जाना जाता है। छह लाख तमिलों को बचाने के लिए यह द्वीप श्रीलंका को दे दी गई थी। हम स्पष्ट थे कि अगर हमारे मछुआरों पर हमला किया गया तो हम इस द्वीप को वापस पाने के लिए आवाज उठाएंगे। लेकिन इन 10 वर्षों में पीएम मोदी ऐसा करने में नाकाम रहें। उन्होंने दावा किया कि इस गिरी हुई रणनीति के साथ भाजपा तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी।

खेल
प्रमुख समाचार

लखनऊ के खिलाफ आज होगी आरसीबी का भिड़ंत

बेंगलुरु। अभी तक अपने प्रदर्शन में निरंतरता

रखने में नाकाम रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ मंगलवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच में बेहतर खेल दिखाकर अपना अभियान पटरी पर लाने की कोशिश करेगी।

आरसीबी की टीम अभी तीन मैच में दो अंक लेकर अंक तालिका में आठवें स्थान पर है। पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों करारी हार के कारण उसका नेट रन रेट भी गड़बड़ा गया है। फाफ डु प्लेसी की अगुवाई वाली आरसीबी की टीम को कम करके नहीं आंका जा सकता है लेकिन उसके खिलाड़ियों को अपने प्रदर्शन में निरंतरता लानी होगी। उसके पास कई स्टार बल्लेबाज हैं लेकिन विराट कोहली को छोड़कर कोई भी अन्य नहीं चल पा रहा है। आरसीबी को अगर अपना अभियान पटरी पर लाना है तो कोहली के अलावा डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, रजत पाटीदार और कैमरन ग्रीन को भी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। शीर्ष और मध्यक्रम के इन बल्लेबाजों की असफलता के कारण आरसीबी को अभी तक निचलेमध्यक्रम के बल्लेबाजों दिनेश कार्तिक, अनुज रावत और महिपाल लोमरोर पर निर्भर रहना पड़ा है। पाटीदार की खराब फॉर्म जारी है और आरसीबी उनको विश्राम देकर सुयस प्रभुदेसाई जैसे खिलाड़ियों को मौका दे सकता है। आरसीबी की चिंता केवल बल्लेबाजी को लेकर नहीं है क्योंकि उसके मुख्य गेंदबाज भी अभी तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उसका तेज गेंदबाजी विभाग मोहम्मद सिराज पर निर्भर है जिन्होंने अभी तक तीन मैच में दो विकेट लिए हैं। यही नहीं वह रनों पर अंकुश लगाने में भी नाकाम रहे हैं। सिराज ने अभी तक 10 रन प्रति ओवर की दर से रन लुटाए हैं। सिराज के साथ नई गेंद संभालने वाले अलजारी जोसेफ ने भी अभी तक केवल एक विकेट लिया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

निफ्टी 135 अंक चढ़ा तो सेंसेक्स 74 हजार के पार

नईदिल्ली। स्थानीय शेयर बाजारों में सोमवार को नये वित्त वर्ष के पहले दिन की शुरुआत मजबूत रही और बीएसई सेंसेक्स 363 अंक के लाभ में रहा। कारोबार के दौरान एक समय दोनों मानक सूचकांक सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी अबतक के ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गये थे। एशिया के अन्य बाजारों में मजबूत रुख तथा विदेशी पूंजी प्रवाह के साथ घरेलू बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही। तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स 363.20 अंक यानी 0.49 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74,014.55 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान, एक समय यह 603.27 अंक चढ़कर अबतक के ऑल टाइम हाई 74,254.62 अंक तक चला गया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 135.10 अंक यानी 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ 22,462 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 203.05 अंक चढ़कर 22,529.95 के रिकॉर्ड स्तर तक चला गया था।

नई प्रौद्योगिकियों ने बैंकिंग को बदल दिया : मोदी

मुंबई। देश के शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के आज 90 साल पूरे हो गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। इस अवसर पर एक सिक्के का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिजर्व बैंक की भूमिका देश के बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाए रखने में अहम और बड़ी रही है। शीर्ष बैंक के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, उससे देश की आम जनता सीधे रुप से प्रभावित होती है। इसने देश के अंतिम व्यक्ति तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आरबीआई दुनिया भर में अपने पेशेवर रवैये और प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता है।

कमर्शियल और एफटीएल सिलेंडरों की कीमतें हुई कम

नई दिल्ली। तेल कंपनियों ने 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर और पांच किलो एफटीएल (फ्री ट्रेड एलपीजी) सिलेंडर की कीमतें कम कर दीं हैं। सूत्रों ने बताया कि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 30.50 रुपये कम की गई है। दिल्ली में एक अप्रैल से इसकी कीमत 1764.50 होगी। पांच किलो एफटीएल की कीमत अब 7.50 रुपये कम हो गई है। एक मार्च को तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद इसका दाम बढ़कर 1795 प्रति सिलेंडर हो गया था। बता दें कि एक फरवरी को इंडेन गैस सिलेंडर की कीमतें मेट्रो शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में अलग अलग थी। एक मार्च के बाद से सभी मेट्रो शहरों में इंडेन गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि देखी गई।

आयकर व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 में लोगों के लिए नई आयकर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं है। व्यक्तिगत करदाता अपना आईटीआर दाखिल करते समय इस व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प चुन सकते हैं। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण सोशल मीडिया पर जारी उन सूचनाओं के बाद दिया जिसमें एक अप्रैल से प्रभावी नई कर व्यवस्था में कुछ बदलावों का दावा किया गया है। मंत्रालय ने कहा, ''एक अप्रैल 2024 से कोई नया बदलाव नहीं किया गया है।'' एक अप्रैल 2023 से शुरू हुए वित्त वर्ष में लोगों के लिए एक संशोधित नई आयकर व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके तहत कर दरें ''काफी कम'' हैं। हालांकि, उसमें पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट तथा कटौती (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ मौजूद नहीं है।

बदल गए टैक्स से जुड़े कई नियम, नई व्यवस्था होगी डिफॉल्ट

जलज मिश्रा

नए वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत एक अप्रैल यानी सोमवार से हो रही है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से हमेशा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि आयकर से जुड़े ज्यादातर बजट प्रस्ताव इसी दिन से लागू होते हैं। एक अप्रैल से कर से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। नई कर व्यवस्था अब डिफॉल्ट बन जाएगी।

कर स्लैब का चयन जरूरी

अगर आप अब तक पुरानी कर व्यवस्था के हिसाब से आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरते आए हैं, तो यह जानना जरूरी है कि देश में एक अप्रैल, 2024 से नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट किया जा चुका है। इसका मतलब है कि आपको हर साल कर स्लैब का चुनाव करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वह अपने आप नई कर व्यवस्था में शिफ्ट हो जाएगा। नई व्यवस्था में कई संशोधन किए गए हैं। इसका मकसद अधिक करदाताओं को इसे चुनने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें सात लाख तक की कमाई करमुक्त है।

स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ

अगर आप नौकरीपेशा हैं और 2024-25 में नई कर व्यवस्था का चुनाव करते हैं तो 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं। इससे आपकी 7.50 लाख तक आय करमुक्त हो जाएगी। 50,000 रुपये की यह छूट पहले पुराने टैक्स स्लैब में ही मिलती थी।

नए स्लैब के तहत कर दरें

सालाना आय- दरें
0 से 3 लाख रुपये- 0%
3 से 6 लाख रुपये- 5%

6 से 9 लाख रुपये- 10%
9 से 12 लाख रुपये- 15%
12 से 15 लाख रुपये- 20%
15 लाख से ज्यादा- 30%

मूल छूट सीमा तीन लाख

नई कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयकर कानून-1961 की धारा 87ए के तहत छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये किया गया है। इसका मतलब है कि नई व्यवस्था में 7 लाख तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं देना होगा क्योंकि वे पूर्ण कर छूट के पात्र हैं।

लीव इनकैशमेंट

अगर आप गैर-सरकारी कर्मचारी हैं तो लीव इनकैशमेंट के रूप में तीन लाख के बजाय 25 लाख रुपये तक पर कर छूट का फायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आयकर कानून की धारा-10(10एए) में प्रावधान किया गया है।

जीवन बीमा

अगर आपकी बीमा पॉलिसी एक अप्रैल, 2023 के बाद जारी हुई है और आपका कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होता है तो मैच्योरिटी पर आपको स्लैब के अनुसार कर देना होगा।

सरचार्ज

अगर आपकी सालाना आय 5 करोड़ रुपये से अधिक है तो आपको 37 फीसदी की जगह अब 25 फीसदी ही सरचार्ज देना होगा।

अन्य जरूरी बातें

व्यक्तिगत करदाता अपनी आय के अनुसार हर साल पुरानी और नई कर व्यवस्था में किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। पेशेवर या व्यावसायिक कंपनियां एक बार ही स्लैब का चयन कर सकती हैं।

अपने शासनकाल में सबसे बड़े ठग सिद्ध हुए कांग्रेसीः भाजपा

आज कांग्रेस 'ठग्स ऑफ छत्तीसगढ़' के नाम से मशहूर हैः ठाकुर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने अप्रैल फूल डे के बहाने से भाजपा पर ठगी करने के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कटाक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए इसे लोकसभा चुनाव में साफ नजर आ रही कांग्रेस की हार की कुंठा से उपजा प्रलाप बताया है। श्री ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बस्तर से टिकट काटकर कांग्रेस आलाकमान ने जो ठगी बैज के साथ की है, दरअसल बैज उस ठगी की पीड़ा और खिसियाहट में जब-तब भाजपा के खिलाफ ऊलजलूल टिप्पणियाँ करके खम्भा नोचने का हास्यास्पद उपक्रम करते रहते हैं। श्री बैज ऐसा करके कांग्रेस के आलाकमान की नजरों में अव्वल बने रहने की होड़ में लगे हैं।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तीन महीनों के अत्यल्प कार्यकाल में जिस तेजी से मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करके दिखाया है, उससे बैज समेत कांग्रेस के तमाम नेता साँसत में हैं। अब जब उनके पास कहने को और कोई विषय या मुद्दा नहीं रह गया है तो वे मिथ्या प्रलाप करके जनता को बरगलाने की फिजूल सियासी कवायद कर रहे हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस की जिस सरकार का अपने पाँच साल के शासनकाल में प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के साथ ठगी करने का शर्मनाक ट्रैक रिकॉर्ड हो, उस कांग्रेस के लोगों को भाजपा पर ठगी करने का कटाक्ष करना कतई शोभा नहीं देता है। जो सबसे बड़े ठग अपने शासनकाल में सिद्ध हुए हैं, वह कांग्रेसी आज ठगी की बात करते हैं तो इससे बड़ा राजनीतिक पाखंड कुछ और नहीं हो सकता।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ठाकुर ने कहा कि जिन्होंने छत्तीसगढ़ में गंगाजल की झूठी कसम खाई पर अपने एक भी वादे को पाँच साल में पूरा नहीं किया, आज वह किस मुँह से भाजपा की तीन माह की सरकार पर तोहमत लगाने का शर्मनाक उपक्रम कर रहे हैं? पूर्ण शराबबंदी का वादा करके उससे साफ मुकरने वाले कांग्रेसी यह कदापि न भूलें कि युवाओं को 15000 करोड रुपए का बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था और वह नहीं दिया। 2 साल का किसानों का बकाया बोनस देने का वादा किया था तो नहीं दिया। संपत्ति कर माफ करने की बात की थी तो नहीं किया, 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात की थी, नहीं लगाई। महिलाओं को 500 रुपए की राशि देने की बात की थी, नहीं दी। महिलाओं को चार सिलेंडर मुफ्त देने की बात कही थी, एक भी नहीं दिया। तो यह जो ठगी कांग्रेस ने की है उसके चलते आज कांग्रेस 'ठग्स ऑफ छत्तीसगढ़' के नाम से मशहूर है।

अली बाबा 40 चोर है इडी गठबंधन के मुखियाःसोनी

सभी भ्रष्टाचारियों का गिरोह जनता को बरगलाने में लगा है- भाजपा सांसद

अपने काले कारनामों से बचने के लिए कांग्रेस इंडी गठबंधन केंद्र की सत्ता पाना चाह रही है लेकिन जनता इन्हें सिखाएगी सबक- भाजपा

रायपुर। अली बाबा 40 चोर की तर्ज पर कांग्रेस ने इंडी गठबंधन बना लिया है। नेशनल हेराल्ड मामले में खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि आज जितने भी इंडी गठबंधन में दल हैं, उन पर भ्रष्टाचार संवैधानिक जांच एजेंसियों ने सच साबित कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन के सभी दल घबराए हुए हैं। उन्हें पता है कि पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी और भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र देखने के आतुर है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी की गारंटी है। ऐसे में राहुल गांधी ही नहीं सभी विपक्षी पार्टियों को यह पता है कि तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता।

भारतीय जनता पार्टी के रायपुर लोकसभा के सांसद सुनील सोनी, महासमुंद लोकसभा सांसद चुन्नी लाल साहू, कांकेर लोकसभा सांसद मोहन मंडावी, जांजगीर चांपा के सांसद गुहाराम अजगले ने संयुक्त रुप से कहा कि राहुल गांधी के साथ-साथ इंडी गठबंधन के दल अपने नेताओं पर भ्रष्टाचार को लेकर हो रही कारर्वाई पर अनर्गल प्रलाप कर पीएम मोदी के बारे में दुष्प्रचार करने में जुटे हैं। जब-जब इन दलों पर भ्रष्टाचार पर कारर्वाई होती है सभी एक-दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। शराब घोटाले में जेल जाने वाले अरविंद केजरीवाल जब सीएम नहीं थे, दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे के साथ कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। जिस कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार का विरोध कर वे दिल्ली की सत्ता पाई आज उसी के साथ मिलकर इंडी गठबंधन कर लिया। पंजाब में भी अरिवंद केजरवाल ने अपनी ईमानदारी का झूठा ढिढोरा पीटकर सत्ता में आए और अब भ्रष्टाचार में फंसे तो अली बाबा 40 चोरों के गिरोह में शामिल हो गए। यही हाल बिहार के चारा घोटाले सहित कई घोटालों के सिरमौर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और झारखंड के हेमंत सोरेन ऐसे परिवारवाद पर खड़ी भ्रष्टाचारी पार्टियों के गिरोह के रूप में इंडी गठबंधन की पहचान बन गई है। अब इनके काले कारनामों से देश की जनता जान और समझ चुकी है और इनके झांसे में आने वाली नहीं है।

भाजपा सांसदों ने कहा कि 70 साल तक कांग्रेसियों और इनके साथ आने गठबधंन करने वाली सभी पार्टियों ने मिलकर देश को लुटने का काम किया। यूपीए की सरकार में तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़ दिए थे। इसके बाद जनता समझ चुकी है, ये भ्रष्टाचारी जब भी सरकार में आएंगे तब-तब ये देश को लूटने का काम करेंगे। जैसे पहले औरंगजेब, बाबर, हुमायूं और मुगलों के साथ अंग्रेजों ने देश को लूटा था। ठीक तरीके से कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों की नीतियां भी हैं, जनता में फूट डालो शासन करो और लूटो। इतना लूटो कि देश ही नहीं इटली और फ्रांस जैसे देशों में अपनी काली कमाई खपाओ। भाजपा सांसदों ने कहा कि एक समय था, जब कांग्रेस सरकार में देश की विदेशी नीतियां अमेरिका, इटली, ब्रिटेन के इशारे पर बनती थी। इन कांग्रेसियों ने भारत देश को विश्व स्तर पर मान को घटा दिया था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है और भारत विश्व गुरू के रूप में स्थापित हो गया है। जिसे अब यहां की पार्टियों को हजम नहीं हो रहा है कि क्योंकि उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, इसलिए वे पीएम मोदी के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी तो विदेशी दौरे पर भारत के लोकतंत्र के खिलाफ बोलने से भी नहीं चूके। अब इन भ्रष्टाचारियों की दाल नहीं गल पा रही है तो बौखला गए हैं।

भाजपा सांसदों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, जिसके मंत्री और विधायक के साथ-साथ भूपेश बघेल ने अपने करीबियों और कांग्रेसियों के मिलकर बड़े-बड़े भ्रष्टाचार किए। लेकिन जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए सत्ता से उखाड़ फेंका। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भ्रष्टाचारियों को ही लोकसभा चुनाव में टिकट दिया है। इसमें खुद छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारियों के सरगना भूपेश बघेल ही हैं, जिन्हें उनके ही पार्टी के नेता और जनता दुत्कार रही है। बिलासपुर के लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव, बस्तर से कवासी लखमा सहित कई नेता हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। इसकी पुष्टि संवैधानिक जांच एजेंसियों ने किया है। कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है, ऐसे में कांग्रेस को मजबूरी में नामी गिरामी इन भ्रष्ट नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना पड़ा। लेकिन जनता इन्हें धूल चटाते हुए पीएम मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। क्योंकि मोदी की सभी गारंटियों को विष्णुदेव की सरकार ने महज तीन माह में पूरा किया है।

रायपुर लोस अंतर्गत तीन विस की महिला मोर्चा की आवश्यक बैठक संपन्न

देश आज मोदीमय हो चुका हैः सुनील सोनी

रायपुर। रायपुर लोकसभा अंतर्गत आज रायपुर जिले के तीन विधानसभाओं की महिला मोर्चा की आवश्यक बैठक लोकसभा कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि आज पूरा देश मोदीमय हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश तेजी से विकसित राष्ट्र बने की ओर अग्रसर है। आगामी लोकसभा चुनाव में हमें रायपुर सहित छत्तीसगढ़ की सभी लोकसभा क्षेत्र में जीत हासिल कर केंद्र में मोदी जी की सशक्त सरकार बनानी है ताकि पिछले दो कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं उससे भी बड़े काम उनके तीसरे कार्यकाल में

होना है। छत्तीसगढ़ में डॉ रमन सिंह जी की सरकार ने जो विकास के कार्य किए थे वह कार्य 2018 से 2023 के बीच में पूरी तरह से बाधित हो चुका था। जिसे भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में पुनः ही बनते ही गति देने का काम कर रही है। और मोदी की गारंटी में जो वादे किए थे उनके अधिकांश वादे 100 दिन में ही पूरी हो गए हैं। हमें जनता के बीच जाकर प्रधानमंत्री के 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां को जनता के बीच पहुंचना है।

रायपुर लोकसभा प्रभारी संदीप शर्मा ने महिला मोर्चा की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की है और उन योजनाओं का लाभ प्रदेश सहित पूरे देश की महिलाओं को मिल रहा है। इस अवसर पर लोकसभा के संयोजक श्री अशोक बजाज जी ने कहा उज्ज्वला योजना से लेकर मातृत्व वंदना योजना सहित लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33त्न आरक्षण से लेकर पंचायत चुनाव में 50त्न भागीदारी महिलाओं की होगी। वहीं दूसरी और प्रदेश की भाजपा सरकार है जो अपनी वादे के मुताबिक प्रदेश की सभी विवाहित महिलाओं को ?1000 प्रतिमाह देने का वादा किया था उसकी भी शुरुआत भाजपा की प्रदेश सरकार ने विगत 10 मार्च को कर दी है। हमें जनता के बीच केंद्र एवं राज्य सरकार की उपलब्धियां एवं महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर जनता को जागरूक करने एवं कांग्रेस की महिला विरोधी नीतियों को लेकर जनता के बीच जाना है। इस अवसर में श्रीमती मीनल चौबे ने कहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच दूरगामी सोच है वह अपने पहले कार्यकाल से ही महिलाओं की सुरक्षा स्वास्थ्य संबंधी सहित अनेक विषयों को लेकर अनेक योजनाएं बनाए हैं। भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए रेडी टू इट निर्माण का कार्य महिलाओं को सौंपा था जिसे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने छीन कर प्रदेश की महिलाओं को बेरोजगार करने का काम किया था। आगामी लोकसभा चुनाव में हमें भ्रष्ट कांग्रेस और उनके गठबंधन के दुष्प्रचार से हमें बचना है और प्रदेश की महिलाओं को इसे अवगत भी करना है। हमें रायपुर लोकसभा में बड़े अंतर से जीत के साथ छत्तीसगढ़ के सभी लोकसभा सीटों में कमल खिलाना है।

कांग्रेस की प्रेस वार्ता पर मंत्री केदार कश्यप का तीखा पलटवार

कांग्रेस की तरह उनकी घोषणाएं भी फर्जी

रायपुर। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की पत्रकार वार्ता पर तीखा पलटवार करते हुए भाजपा के वरिष्ठ मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस की कई फर्जी घोषणाओं को छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 के चुनाव में भी सुना था घोषणाएं पूरी नहीं हुई कांग्रेस पार्टी की तरह ही कांग्रेस की घोषणाएं भी फर्जी हैं झूठ का पुलिंदा जनता इसके कई प्रमाण देख चुकी है।

कश्यप ने कहा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने महिलाओं को रु. 500 देने का वादा किया था 5 साल में एक भी महिला को रु. 500 की राशि नहीं दी गई। जिन लोगों ने 5 साल रु. 500 नहीं दिया अब वह रु. 8000 प्रति महीना देने का वादा कर रहे हैं और यह कहने में उन्हें किसी प्रकार की कोई शर्म भी नहीं आ रही है यही कारण है कांग्रेस पूरी तरीके से हर जगह से खदेड़ी जा रही है। कश्यप ने कहा कि किसान के साथ न्याय की बात करने वाली कांग्रेस सरकार जब केंद्र में 10 वर्ष थी तब धान खरीदी का 10 वर्षों में किसानों को कल 4.4 लाख करोड़ ही भुगतान किया था जबकि मोदी जी की सरकार ने 12 लाख करोड़ से ज्यादा का भुगतान किया जब यह सरकार में रहते हैं तब कुछ करते नहीं और जब विपक्ष में आते हैं तो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। युवा न्याय के विषय पर श्री कश्यप ने कहा कि छत्तीसगढ़ में युवाओं के हक को कांग्रेस ने किस प्रकार मारा किस प्रकार पीएससी घोटाला किया, किस प्रकार नौकरी देने का वादा पूरा नहीं किया, किस प्रकार युवाओं का 15 हजार करोड़ का बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किस प्रकार कांग्रेस सरकार से तंग होकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को नग्न प्रदर्शन करना पड़ा यह सब ने देखा है और युवाओं ने अपने साथ हुए अत्याचार के खिलाफ ही सरकार को उखाड़ फेंका,युवाओं के साथ इतना अन्याय करने वाली कांग्रेस फिर से युवाओं के साथ न्याय की नई घोषणाएं कर रही हैं यह हास्यप्रद है। कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो पत्रकारों के सवाल के जवाब में यह तक नहीं बता पाए की कितनी गरीब महिलाओं को वह ?1 लाख प्रति वर्ष देंगे? क्योंकि देश में अगर वह 50 करोड़ महिलाओं को भी यह राशि देंगे तो उसके लिए 50 लाख करोड रुपए की आवश्यकता होगी और इतना ही देश का एक साल का बजट है अतः यह सभी घोषणाएं कांग्रेस की तरह फर्जी है।

छत्तीसगढ़/राजधानी — प्रमुख समाचार

शराब की नई दरें बीती रात से लागू, कोई नया दुकान नहीं

रायपुर। राज्य में वर्ष 24-25 के लिए शराब की नई दरें बीती रात से लागू कर दी गई हैं। आबकारी विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है। यह दर काउंटरवेलिंग ड्यूटी और आबकारी शुल्क को छोडकर् तय की गई है। इसे लेकर विभाग ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। इस वर्ष बताया जा रहा है कि 11 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा गया है। इस बार दुकान नहीं बढ़ाई गई है। पूरा कारोबार पुरानी 630 से अधिक दुकानों से ही होगा। आबकारी विभाग की ओर देसी-विदेशी शराब की नई कीमत जारी कर दी है। आदेश के अनुसार नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमत बढ़ाई गई है। प्रदेश में अब आज से क्वार्टर में 10 रुपये और बोतल में 40 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इ आबकारी विभाग ने बताया कि 1 अप्रैल से एक्साइज ड्यूटी के साथ शराब की ब्रिकी शुरू हो गई है। नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया है। बताया जाता है कि प्रदेश में देसी शराब की एक्साइज ड्यूटी 7 साल से बढ़ी नहीं है। इसी तरह विदेशी शराब में विगत कई साल से एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ी है। यहीं कारण है कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से शराब के शौकीनों के जेब पर इसकी विपरीत असर पड़ेगा।

निगम आयुक्त पहुंचे खारुन सफाई के दिए निर्देश

रायपुर। नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने सोमवार को खारून नदी की व्यवस्थित सफाई का जायजा लेने पहुंचे इस दौरान उन्होंने निगम के अधिकारियों को निर्देशित देते हुए कहा कि वे सिंचाई विभाग से समन्वय कर इसकी सफाई करवाएं। इसके अलावा उन्होंने चिंगरी नाला निर्माण कार्य तेजी से करवाने, चंदनीडीह एसटीपी में उपचारित जल का औद्योगिक पुनर्पयोग करने के निर्देश दिए साथ ही सरोना में कचरे को उपचारित कर हटाए जा रहे कार्य को देखा। निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने 6 एमएलडी क्षमता के भाठागांव एसटीपी, 75 एमएलडी क्षमता के चंदनीडीह एसटीपी का निरीक्षण किया साथ ही सरोना में पुराने कचरे के ढेरों को उपचारित करके हटाए जाने के कार्य का अवलोकन कर इंटेकवेल, चिंगरी नाला निर्माण कार्य की प्रगति को प्रत्यक्ष देखा। आयुक्त ने खारून नदी की व्यवस्थित सफाई सिंचाई विभाग के साथ समन्वय करके शीघ्र करवाना सुनिति करवाने के निर्देश दिये है।

नहीं मिली 1000 करोड़ की लंबित राशि तो अस्पतालों में ताला लग जायेगा

रायपुर। धानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान योजना एवं मुख्यमंत्री विशिष्ट स्वास्थ्य योजना छत्तीसगढ़ सरकार के भुगतान हेतु ध्यानाकर्षण दिलाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान एव मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को कांग्रेस नेताओं ने एक स्मरण पत्र सौंपा और तत्काल लंबित राशि भुगतान करने की मांग की अन्यथा कई अस्पतालों में ताला लग जायेगा। प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डा. राकेश गुप्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य जन आरोग्य योजना आयुष्मान योजना तथा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सूची के अधिकांश अस्पताल पिछले कुछ माह से बंद होने की कगार पर है। ज्ञात हो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं का करीब 1000 करोड रुपए से अधिक का भुगतान लंबित है। बार-बार अनुरोध एवं स्मरण पत्र देने के बावजूद राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों की सहायता के लिए बनाई गई इस योजना में भुगतान न होने से सैकड़ों अस्पताल बंद होने की कगार पर है। छोटे अस्पतालों के संचालक लोन और दवाई की बिल सहित अपने स्टाफ को तनख्वाह देने में असमर्थ हैं। अनुरोध है कि तत्काल फंड की व्यवस्था कर आपात स्थिति को समझते हुए भुगतान की व्यवस्था करें।

मोबाइल एप्स के जरिए मतदाताओं तक पहुंच रही है निर्वाचन संबंधी हर जानकारी

रायपुर। निर्वाचन में सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीकें अहम भूमिका निभा रही हैं। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी एवं सहभागिता बढ़ाने में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत निर्वाचन आयोग नई तकनीकों और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग निर्वाचन को और ज्यादा सुगम, निष्पक्ष तथा समावेशी बनाने में कर रहा है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक का जागरूक और सजग रहना जरूरी है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रौद्योगिकी आधारित मोबाइल एप्स विकसित कर उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया है। आयोग द्वारा विकसित विभिन्न मोबाइल एप्स के उपयोग से मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहभागिता और सुविधा दोनो बढ़ी है। वोटर हेल्पलाइन एप से मतदाता अपना मतदाता परिचय पत्र (एपिक) नम्बर डाल कर बहुत ही आसानी से अपने विधानसभा, पोलिंग बूथ एवं मतदाता सूची में सरल क्रमांक पता कर सकते हैं। यदि एपिक नंबर नहीं मालूम है तो मतदाता अपना विवरण जैसे कि नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र, लिंग एवं निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी भरकर अपना नाम मतदाता सूची में खोज सकते हैं। यदि मतदाता का मोबाइल नंबर मतदाता सूची में पंजीकृत है तो मतदाता अपना ई-एपिक भी डाउनलोड कर सकता है।

सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरिये गिरफ्तार

रायपुर। बीरगांव निगम दफ्तर के पास बोलेनो कार में आईपीएल क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 4 सटोरिये को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक लैपटॉप, 7 मोबाईल फोन, बोलेनो कार सहित लाखों रुपये का सट-पट्टी का हिसाब जप्त किया। शुभ-लाभ 0543 नामक एप से सट्टा खिला रहे थे। बीरगांव स्थित नगर निगम आफिस के पास चारपहिया में सेटअप तैयार कल शाम रात हो रहे आई.पी.एल. क्रिकेट मैच में रन, विकेट, कैच आदि पर शुभ-लाभ 0543 नामक एप से सट्टा खिला कर रहे थे। इसकी सूचना मिलती ही पुलिस ने एक टीम को वहां भेजा चार सटोरियों को गिरफ्तार किया जिनके पास से एक लैपटॉप, 7 मोबाईल फोन, 60,000 रूपये, लाखों रूपये का सट्टा पट्टी का हिसाब तथा सट्टा संचालन में प्रयुक्त बोलेनो कार सी जी/04/पी वी/1659 जब्त किया गया। इनकी कुल कीमत लगभग 7,00,000 रूपए बताई गई है। सटोरियों के विरूद्ध थाना उरला पुलिस ने 166/24 धारा 4 (क) जुआ एक्ट एवं छ.ग. जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 07 का अपराध दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में अजय देवांगन, दीपक खंडपुर, खिलेश्वर देवांगन एवं राकेश सिंह राजपूत शामिल है, सभी आरोपी रायपुर के रहने वाले है।

क्रेडा के पूर्व सदस्य ने पूर्व सीएम को पत्र लिखकर दी नसीहत

कम से कम अपनों की ही सुन लीजिए भूपेश बघेलः भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने कांग्रेस में फूटे एक और लेटर बम पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि - भूपेश बघेल, हमारी नहीं तो कम से कम अपनों की ही सुन लीजिए? आखिर इतनी हठधर्मिता किस बात की है? हमें लगता हैं आप और आपकी कांग्रेस पार्टी को देश के लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं पर रत्तीभर भी विश्वास नहीं रह गया है क्या? रोजाना आप और आपकी कांग्रेस पार्टी इन पर सवाल उठातीं रहतीं है।

प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि जब-जब कांग्रेस पार्टी देश में चुनाव जीतती है तो ईवीएम ठीक रहती हैं और यदि चुनाव हार जाती हैं तो उस हार की ?जिम्मेदारी न लेना पड़े ईवीएम पर ठीकरा फोड़ देते हैं इसे हार की बौखलाहट निकालना कहते हैं।? छत्तीसगढ़ में संपन्न हुए 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया उसी के बाद से कांग्रेसी विचलित हो गये है। और अनर्गल टिप्पणियां करते हुए अपनी खीझ निकाल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो खुद लोकसभा चुनाव लड़ने से बच रहे थे पार्टी ने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से उनको उम्मीदवार घोषित किया।? इसके बाद से ही उनकी उम्मीदवारी का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने कहा कि सबसे पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य ने भरे मंच से उनके कायर्काल और कार्यप्रणाली को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर यहां तक कह डाला कि भूपेश बघेल की उम्मीदवारी वापस होनी चाहिए क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। कांग्रेस के एक महामंत्री ने भी पार्टी फंड का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाते हुए हाई कमान को पत्र लिखकर अवगत कराया था। अब क्रेडा के पूर्व सदस्य ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर ये नसीहत दे डाली कि जब 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता ने बंपर बहुमत देकर सरकार बनाई तब ईवीएम ठीक थी, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं खड़ा किया गया? प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने भूपेश बघेल की उस नसीहत पर भी निशाना साधा कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारे तो चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होगा। कांग्रेस पार्टी में जब कोई निष्ठावान कार्यकर्ता, नेता आवाज उठाता है, तो उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर नोटिस जारी कर दिया जाता है ।

गर्मी का प्रकोप, सुबह लगेगी स्कूल

रायपुर। इन दिनों तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान में बढ़ोत्तरी से लोगों का हाल-बेहाल कर दिया है। जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंन लगातार बढ़ते तापमान और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्कूलों के समय में बदलाव करने का फैसला लिया है। बता दें कि राजधानी रायपुर में तेजी से गर्मी बढ़ने लगी है। इसके चलते स्कूली जिला शिक्षा अधिकारी ने बच्चों की टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है। दोपहर की चिलचिलाती धूप के कारण बच्चे परेशान हो रहे थे। इसलिए स्कूल टाइमिंग में बदलाव किया गया है। जिसमें अब दो पाली में स्कूल लगेगी। जिसमें सरकारी स्कूल सुबह 7.30 से 11.30 बजे तक चलेगी। गौरतलब है कि अभी स्कूलों में वार्षिक परिक्षाएं चल रही है। वहीं ज्यादातर परिक्षाएं सुबह की पहली पाली में हो रही हैं वहीं जहां कक्षाएं लग रही है शिक्षा विभाग ने उन स्कूलों के समय में बदलाव किया है। रायपुर जिले के अंतर्गत आने वाले स्कूलों के समय में जिला शिक्षा अधिकारी ने टाइमिंग में बदलाव किया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.